My Notes....

राष्ट्रीय

जीएसएलवी मार्क तीन का सफल प्रक्षेपण

पिछले पचास साल के दौर में भारत ने **मंगलयान, चंद्रयान, मौसम आधारित उपग्रहों को प्रक्षेपित कर दिया है** कि अब वो अमेरिका और रूस को टक्कर देने को तैयार है। इसरो ने 5 जून को फिर कहानी लिख दी है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से **जीएसएलवी मार्क तीन** का प्रक्षेपण किया गया। **करीब 300 करोड़ की लागत और 15 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद जीएसएलवी मार्क 3 का निर्माण किया गया है।** अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसे मास्टर रॉकेट का नाम दिया है। जीएसएलवी मार्क 3 की ऊंचाई 13 मंजिला इमारत के बराबर है और ये चार टन वजनी सेटेलाइट को अपने साथ ले जा सकता है।

क्या है

1. वर्तमान में भारत को 2.3 टन वजनी संचार सेटेलाइट को लांच करने के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। **जीएसएलवी मार्क 3 अपने साथ करीब चार टन वजनी जीसैट-19** को अपने साथ ले जाएगा। इस रॉकेट के कामयाब प्रक्षेपण से भारत खुद पर निर्भर होने के साथ व्यवसायिक इस्तेमाल कर सकेगा।
2. जीएसएलवी मार्क 3 के प्रक्षेपण में **स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन** का इस्तेमाल किया गया है। **क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है।**
3. स्पेस में मानव को भेजने के लिए इसरो ने केंद्र सरकार से 12,500 करोड़ रुपये की मदद मांगी है। अगर केंद्र की तरफ से मदद मिली को इसरो सात साल में मानव को अंतरिक्ष में रख सकेगा।
4. **ह्यूमन स्पेस मिशन की तैयारी इसरो पहले ही कर चुका है।** 2014 में स्पेस स्यूट और क्रू माड्यूल को तैयार किया गया था।
5. स्पेस एजेंसी की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया कि भारत की तरफ से किसी महिला को स्पेस मिशन पर भेजा जाना चाहिए।
6. **अब तक रूस, अमेरिका और चीन अंतरिक्ष में मानव को भेज चुके हैं।** 12 अप्रैल 1961 को रूस के यूरी गागरिन वोस्टोक 1 स्पेसक्रॉफ्ट के जरिए स्पेस मिशन में कामयाबी हासिल की थी।
7. अमेरिका ने एक महीने बाद 5 मई 1961 को एलन वी शेपर्ड को फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में भेजा था।
8. भारत के रमेश शर्मा 1984 में इसरो और रूस के संयुक्त अभियान में स्पेस पर झंडा गाड़ने में कामयाब रहे।

मौजूदा रॉकेटों की क्षमता कम

1. अभी इसरो के पास दो प्रक्षेपण रॉकेट हैं। इनमें पोलर सेटेलाइट लॉन्च वेहिकल सबसे भरोसेमंद है। इससे अंतरिक्ष में 1.5 टन वजनी उपग्रह भेजे जा सकते हैं।
2. दूसरा जीएसएलनी मार्क 21 है इसकी मदद से 2 टन वजनी उपग्रह भेजे जा सकके हैं। लेकिन इसे भरोसेमंद नहीं माना जाता है।
3. इसरो अभी 4 टन भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए फ्रांस के एरियन-5 रॉकेट की मदद लेता है।

क्या है जीएसएलवी

1. जीएसएलवी की मदद से सेटेलाइट को पृथ्वी से 36000 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया जाता है।
2. यह कक्षा भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के सीध में होती है। जीएसएलवी यह काम तीन चरण में करता है जिसमे अंतिम चरण में सबसे अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव वाले क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए जिस निर्धारित वेग को प्राप्त करना होता है वो बहुत अधिक होता है जिसकी वजह से अधिक से अधिक ताकत की जरूरत होती है।

जीएसएलवी मार्क-3 का निर्माण

1. **इसरो ने जीएसएलवी मार्क-3 का निर्माण 2000 के दशक में शुरु किया।** पहले इसका प्रक्षेपण 2009-10 में प्रस्तावित था। लेकिन कई वजहों से ये टलता रहा। इसमें तीन रॉकेट स्टेज हैं।
2. **18 दिसंबर 2014 को क्रायोजेनिक इंजन के साथ इसका पहला सब ऑर्बिटल परीक्षण हुआ।** 2010 में 24 जनवरी, पांच मार्च और आठ मार्च को इसके कई तकनीकी परीक्षण हुए।
3. 25 जनवरी 2017 को क्रायोजेनिक इंजम स्टेज का 50 सेकेंड का परीक्षण हुआ। क्रायोजेनिक इंजन का सबसे लंबा परीक्षण 640 सेकेंड तक 18 फरवरी को पूरा हुआ। इन परीक्षणों में इस रॉकेट की क्षमताओं को परखा गया।

"स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ" अभियान की शुरूआत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौशल विकास हेतु **स्किल फोर लाइफ, सेव अ लाइफ अभियान की शुरूआत की**। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि भारत जन-सांख्यकीय लाभ की स्थिति में है क्योंकि भारत की **65 फीसदी से अधिक आबादी 35 वर्ष की आयु से नीचे है।** सरकार ने इस स्थिति में युवाओं को जरूरी कौशल देकर **सतत और समेकित विकास की मजबूत आधारशिला रखना सुनिश्चित किया है।**

क्या है

1. **"स्किल्स फोर लाइफ, सेव अ लाइफ" अभियान** का उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली में प्रशिक्षित लोगों की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाना है। इस अभियान तहत कई पाठ्यक्रमों को शुरू करने की योजना है। जिसके तहत हैल्थ केयर के क्षेत्र में अलग-अलग योग्यताओं वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा साथ ही आम लोगों को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
2. समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि युवाओं के कुशल होने से उन्हें शीघ्र रोजगार मिलता है और इससे देश समृद्ध होगा। श्री नड्डा ने कहा कि इससे युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीदों वास्तविक नौकरियों की उपलब्धता के बीच अंतर कम होगा।
3. कुशलता से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती और प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षित कुशल मानव संसधान की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम होता है। देश में स्वास्थय के क्षेत्र में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यापक संभावनाएं है। ऐसी पाठ्यक्रमों के शुरू होने से स्वास्थ्य क्षेत्र को पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मी मिल सकेंगे।
4. सभी कोर्सों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान और अखिल भारतीय आर्युविज्ञान नई दिल्ली में तैयार किया है।

भारत की पहली ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना

विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ **एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड** के माध्यम से **भारत सरकार आंध्र प्रदेश के सात जिलों की ग्राम पंचायतों में 10 लाख परंपरागत स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी लाइट लगायेगी।** यह भारत सरकार की स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय परियोजना (एसएलएनपी) के तहत देश में ग्रामीण एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग से जुड़ी पहली परियोजना है। प्रथम चरण में गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुर और चित्तूर जिलों की ग्राम पंचायतों में यह बदलाव सुनिश्चित किया जायेगा।

क्या है

1. ग्रामीण क्षेत्रों में इस बदलाव अभियान से **ग्राम पंचायतों को हर साल कुल मिलाकर लगभग 147 मिलियन यूनिट बिजली की बचत करने में मदद मिलेगी** और इससे 12 करोड़ टन कार्बन डाई ऑक्साइड (सीओ2) की रोकथाम संभव हो पायेगी।
2. इस परियोजना पर आने वाली कुल पूंजीगत लागत का **वित्त पोषण एजेंसे फ्रांकेइसे डे डेवलपमेंट (एएफडी) नामक फ्रांसीसी विकास एजेंसी** द्वारा किया जायेगा।
3. इस परियोजना के तहत ईईएसएल अगले 10 वर्षों तक इन ग्राम पंचायतों में समस्त वार्षिक रख-रखाव और वारंटी प्रतिस्थापन का कार्य करेगी।

4. इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वर्ष 2018 तक राज्य के समस्त गांवों में लगभग 30 लाख परंपरागत स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई जायेंगी। ईईएसएल ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि 10 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने से बिजली में लगभग 59 प्रतिशत की बचत होगी जो 88.2 करोड़ रुपये की वार्षिक मौद्रिक बचत के बराबर है।
5. राष्ट्रीय स्तर पर भारत के 21 राज्यों में 23 लाख से भी ज्यादा परंपरागत स्ट्रीट लाइट के स्थान पर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं।

आरएसईटीआई दिवस 2017

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की बहु-आयामी रणनीति के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत कौशल विकास हेतु दो पहल की हैं।** प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम डीडीयू-जीकेवाई, जो कौशल और सुनिश्चित वेतन वाला रोजगार उपलब्ध करायेगा। **देश में 587 ग्रामीण स्व रोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई)** के माध्यम से कौशल विकास, जो कौशल उपलब्ध करायेंगे। इससे प्रशिक्षु बैंकों से ऋण लेने और अपना लघु उद्यम शुरू करने में सक्षम होंगे।

क्या है

1. विभिन्न राज्यों में **आरएसईटीआई** के शानदार प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए मंत्रालय **चौथा आरएसईटीआई दिवस मना रहा है।** वर्ष 2014-15 और 2015-16 में सर्वोतम प्रदर्शन करने वाले राज्यों, आरएसईटीआई का संचालन करने वाले अग्रणी बैंकों और आरएसईटीआई के निदेशकों को कुल 88 पुरस्कार दिये गए।
2. अलग-अलग वर्गों में सर्वोतम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और छत्तीसगढ़ शामिल रहे। सर्वोतम प्रदर्शन करने वाले बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, आईसीआईसीआई और आंध्रा बैंक रहे।
3. सर्वोतम प्रदर्शन करने वाली आरएसईटीआई में एसबीआई विजयनगरम, एसबीआई विशाखापत्तनम, पीएनबी गया, केनरा बैंक हलिअल और देवांगरे, सिंडिकेट बैंक मणिपल और मेरठ, आंध्रा बैंक श्रीकुलम, आईसीआईसीआई जोधपुर और उदयपुर व अनंतपुर और बीजापुर के ग्रामीण विकास एवं स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआई) शामिल रहे।
4. **वर्तमान में देश में 587 आरएसईटीआई काम कर रहे हैं जो 37 प्रायोजक बैंकों के साथ भागीदारी करके 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत हैं।** आरएसईटीआई ने 22 लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया है और इनमें से 13 लाख स्व रोजगार में लगे हुए हैं। इनमें से 6 लाख प्रत्याशियों को ऋण संयोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
5. आरएसईटीआई ने अपने पाठ्यक्रम को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के सामान्य मानदंडों के साथ जोड़ा है। यह एनएसक्यूएफ से जुड़े 56 पाठ्यक्रमों में कौशल प्रदान करते हैं। जिनकी रूपरेखा विशेष रूप से उद्यमिता विकास के लिए तैयार की गई है।
6. चौथा आरएसईटीआई दिवस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। उन्होंने सतत आजीविका के लिए ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

''साथ'' कार्यक्रम का शुभारंभ

नीति आयोग ने सहकारी संघवाद की कार्यसूची पर अमल के लिए **''साथ'' यानी 'सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल'** अर्थात् मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए स्थायी कार्यक्रम नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का **लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का कायाकल्प करना है।** यह कार्यक्रम विभिन्न राज्यों द्वारा नीति आयोग से अपेक्षित तकनीकी सहायता की आवश्यकता पूरी करेगा।

क्या है

1. **''साथ'' का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए राज्यों के तीन भावी 'रोल मॉडलों' का चयन करना** और उनका निर्माण करना है।
2. नीति आयोग अंतिम लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्यों की मशीनरी के साथ सहयोग करते हुए हस्तक्षेप का **सुदृढ़ रोडमैप तैयार करेगा, कार्यक्रम कार्यान्वयन का ढांचा विकसित करेगा** और **निगरानी एवं अन्वेषण व्यवस्था कायम करेगा।** इसके अंतर्गत संस्थागत उपायों के जरिए राज्यों की विभिन्न प्रकार की सहायता की जाएगी।
3. नीति आयोग ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आमंत्रित किया था, जिनमें से **14 राज्यों ने अपने प्रेजेंटेशन किए** जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोआ, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
4. इन राज्यों ने अपने परियोजना प्रस्ताव नीति आयोग के सदस्य श्री विवेक देबराय की अध्यक्षता वाली एक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए।
5. **इन 14 राज्यों में से पांच का चयन किया गया है।** इनमें से 3 राज्यों का चयन अंतिम रूप से किया जाना है, जिनमें यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
6. राज्यों का अंतिम चयन विभिन्न स्वास्थ्य मानदंडों जैसे **प्रसूति मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मलेरिया के मामले आदि के आधार पर किया जाएगा।**

भारत ने बाल श्रम पर आइएलओ के दो समझौतों की पुष्टि की

भारत ने बाल श्रम पर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के दो समझौतों की पुष्टि कर दी। ये समझौते बाल श्रम के सबसे खराब तरीके को खत्म करने प्रति विश्व की प्रतिबद्धता और बच्चों को **न्यूनतम बुनियादी शिक्षा दिलाने के लिए किए गए हैं।** केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने समझौतों की पुष्टि के दस्तावेज आइएलओ को सौंपे।

क्या है

1. आइएलओ ने भारत द्वारा बाल श्रम के खिलाफ उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने दोनों समझौतों की पुष्टि की थी।
2. **समझौता संख्या 138 रोजगार के लिए न्यूनतम आयु से संबंधित है और समझौता संख्या 182 बाल श्रम के खराब तरीकों को खत्म करने की तत्काल कार्रवाई से संबंधित हैं।**
3. नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी ने समझौते की पुष्टि करने पर भारत की सराहना की।

50 साल पुराना कानून बदला

केन्द्र सरकार ने 5 जून को **भ्रष्टाचार से संबंधित कानून में एक बड़ा संशोधन किया है।** 50 साल पुराने कानून को बदलते हुए केन्द्र सरकार ने **भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध करने के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया है।**

क्या है

1. केन्द्र सरकार के नए कानून के मुताबिक, **अब किसी भी कर्मचारी पर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसे छह महीने में साबित करना होगा।**
2. सरकार ने ये कदम ऐसे मामलों की जांच में गति लाने के उद्देश्य से किया है। अकसर ऐसे मामलों में ये देखने में आता है कि ये मामले लंबे समय तक लंबित रहते हैं।
3. **डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 में संशोधन किया है।** इसमें जांच और जांच की कार्रवाई के लिए समय सीमा तय की है।
4. संशोधित कानून के मुताबिक, जांच करने वाली संस्था को जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है।

पेरिस समझौते से अलग हुआ अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पर्यावरण संरक्षण पर हुए ऐतिहासिक पेरिस समझौते से अलग होने का एलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह **पर्यावरण के मुद्दे पर नए समझौते के लिए चर्चा करेंगे।** अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इस फैसले के संकेत **जी-7 सम्मेलन** में पहले ही दे दिये थे। इस बात की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि **भारत और चीन के लिए पेरिस समझौते** का पालन करना इतना मुश्किल नहीं है जितना अमेरिका के लिए है। इस बीच पेरिस के मेयर ने ट्रंप के इस एलान को बड़ी गलती करार दिया है।

क्या है

1. **करीब 200 देशों के साथ 2015 में पेरिस में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद अहम समझौता हुआ था।** ट्रंप ने विगत शनिवार को इटली के सिसली में संपन्न विकसित देशों के संगठन जी-7 की बैठक में इसके संकेत दिए थे। उन्होंने तब पर्यावरण परिवर्तन समझौते को और बढ़ावा देने से इन्कार कर दिया था।
2. **भारत, चीन, कनाडा और यूरोपीय संघ ने पेरिस समझौते के तहत किए गए वादे पर टिके रहने की बात कही है। माना जाता है** कि ट्रंप ने अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (ईपीए) के प्रशासक और तेल उद्योग जगत के सहयोगी स्कॉट प्रूइट के साथ मिलकर पेरिस समझौते से बाहर होने की शर्तो पर काम किया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के पेरिस समझौते से मुंह फेरने के फैसले से अमेरिका के अभिन्न सहयोगी समझे जाने वाले यूरोपीय देश भी ट्रंप के फैसले से अलग हो सकते हैं।
3. तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा के **अथक प्रयासों के चलते वर्ष 2015 में अमेरिका समेत तकरीबन 200 देशों ने पेरिस में करार पर हस्ताक्षर किया था।** इसके तहत साल 2025 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 26 से 28 फीसद (वर्ष 2005 के स्तर से) तक की कमी लाने पर सहमति बनी थी। साथ ही अविकसित और विकासशील देशों को रियायती दरों पर ग्रीन टेक्नोलॉजी मुहैया कराने के साथ आर्थिक पैकेज देने की भी बात कही गई थी।
4. **पेरिस समझौते से औपचारिक तौर पर हटने में तकरीबन तीन साल का वक्त लगेगा।** बहुमत दल के नेता मिच मैक्कोनेल समेत सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के 22 सीनेटरों ने ट्रंप को पत्र लिखकर करार से हटने का आग्रह किया था। राष्ट्रपति का फैसला उसी से प्रभावित बताया जा रहा है। **चीन के बाद अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है।**

क्या है पैरिस समझौता?

1. पैरिस जलवायु समझौते को पिछले साल दिसंबर में अंतिम रूप दिया गया था। इससे जुड़े देशों को उन कदमों पर अमल करना होगा, जिससे वैश्विक तापमान में औसत बढ़ोतरी 2 डिग्री से ज्यादा न हो।
2. पैरिस अग्रीमेंट के लिए पहल करने वाले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पद छोड़ने से पहले अमल देखना चाहते थे, इसके लिए वह कई देशों से खुद संपर्क में थे।
3. यह अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि ट्रंप राज में अमेरिका पैरिस डील से अलग हो जाएगा। ट्रंप काफी पहले से क्लाइमेट चेंज की थिअरी पर ही सवाल उठाते रहे हैं।
4. कहा जा रहा है कि पैरिस अग्रीमेंट से अलग होने से पहले अमेरिका को तीन साल का इंतजार करना होगा और एक साल का नोटिस भी देना होगा।
5. प्रावधान है कि अमीर देश फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, सो उन्हें इसके मद में गरीब और विकासशील देशों को मदद करनी होगी।
6. सीरिया और निकारागुआ को छोड़ कर सभी देश इससे जुड़े हैं। भारत सरकार ने पिछले साल 2 अक्टूबर को पैरिस अग्रीमेंट की पुष्टि कर दी थी।
7. कुल उत्सर्जन में भारत का हिस्सा 4 प्रतिशत के करीब है। चुनौती यह है कि सरकार मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा विस्तार देगी। बिजली उत्पादन कोयले पर आधारित है।

गंगा विधेयक मसौदे पर गठित समिति की पहली बैठक

गंगा विधेयक 2017 के मसौदे के प्रावधानों पर मंथन के लिए गठित समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन** के महानिदेशक श्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गंगा विधेयक के मसौदे से जुड़े विभिन्न पहलुओं, परिभाषाओं और अध्यायों पर मंथन किया गया। बैठक में मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री संजय कुंडु, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता श्री पुरूशैन्द्र कौरव तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अरूण कुमार गुप्ता ने भाग लिया।

क्या है

1. **जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 'राष्ट्रीय नदी गंगा (पुर्नरूद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) विधेयक 2017'** के मसौदे के विभिन्न प्रावधानों पर विचार-विमर्श के लिए इस समिति का गठन किया है।
2. **इस विधेयक के तहत गंगा नदी की निर्मलता एवं अविरलता को नुकसान पहुंचाने वालों पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।** यह समिति कृषि, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की मांग के चलते गंगा नदी पर बढ़ते दबाव एवं उसकी धारा की निरंतरता को बनाए रखने जैसी चुनौतियों पर भी विचार कर रही है।
3. उल्लेखनीय है कि देश में इस तरह के विधेयक के लिए पहली बार प्रयास हो रहा है जिसके तहत गंगा नदी के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अत्याधिक कठोर प्रावधान किए जाएंगे। विधेयक में गंगा नदी से जुड़े उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और राष्ट्रीय हरित अभिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों को भी समाहित किया गया है।
4. इस प्रस्तावित विधेयक का मसौदा इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि यह आने वाले दिनों में देश की अन्य नदियों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए एक आदर्श विधेयक साबित हो।
5. **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जुलाई 2016 में नदी गंगा की निर्मलता और अविरलता** को बनाए रखने के लिए इस विधेयक के मसौदे को तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) गिरिधर मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
6. समिति ने इस विधेयक का मसौदा 12 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय जल संसाधन, गंगा सरंक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती को सौंपा था।

पहली यात्रा पर निकली खंडेरी

स्कॉर्पीन श्रेणी की छह पनडुब्बियों में से दूसरी पनडुब्बी खंडेरी मुम्बई हार्बर से अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकल गई है, पनडुब्बी को कड़े परीक्षणों के बाद भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि **खंडेरी अपनी पहली समुद्री यात्रा पर निकल गई।** यह उसके प्रणोदन संयंत्र का पहला प्रमुख परीक्षण है। अधिकारी ने कहा, 'सफल परीक्षण के बाद पनडुब्बी इस वर्ष भारतीय नौसेना में शामिल होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ जाएगी। अब उसे कड़े परीक्षणों से गुजरना होगा।'

क्या है

1. **स्कॉर्पीन क्लास की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी** को 12 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था।
2. इसकी लॉन्चिंग के मौके पर मझगांव डॉक लिमिटेड शिपयार्ड पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे भी मौजूद थे। भामरे ने उस दौरान कहा था कि वह दिन दूर नहीं जब हम दूसरे देशों के लिए भी सबमरीन बनाएंगे।
3. **स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियां डीजल और बिजली से चलती हैं।** मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल जंग में हमले के लिए होता है। आईएनएस खंडेरी में दुश्मनों की नजर से बचने के लिए स्टील्थ फीचर है।

4. इसके अलावा, यह दुश्मन पर प्रीसेशन गाइडेड मिसाइल के जरिए सटीक और घातक हमला कर सकता है। हमले करने के लिए इसमें पारंपरिक टारपीडो के अलावा ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जिसे पानी के अंदर या सतह से दागा जा सकता है।
5. **यह सबमरीन उष्णकटिबंधीय मौसम समेत किसी भी हालात में ऑपरेट करने में सक्षम है।** इसमें कम्यूनिकेशन से जुड़े अत्याधुनिक डिवाइस लगी हुई हैं। किसी भी अत्याधुनिक सबमरीन की तरह ही इससे कई तरह के मिशनों (ऐंटी सरफेस और ऐंटी सबमरीन, खुफिया सूचनाएं जुटाना, माइन बिछाना, इलाके की निगरानी आदि) को अंजाम दिया जा सकता है।
6. खंडेरी का नाम मराठा लड़ाकों के एक द्वीप पर स्थित किले पर पड़ा है। उन्हें इस किले की वजह से 17वीं शताब्दी में समुद्र पर अपना वर्चस्व कायम करने में मदद मिली।

भारत ने कम दूरी की देशी मिसाइल का टेस्ट किया

भारत ने स्वदेश विकसित तीव्र प्रतिक्रिया वाली जमीन से हवा में मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल का 4 जून को ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि **यह मिसाइल 20 से 30 किलोमीटर तक की दूर पर तक के लक्ष्य को भेद सकती है।**

क्या है

1. **यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में भी सक्षम है।** यह तेजी से प्रतिक्रिया करने वाली मिसाइल है।
2. यह हर तरह के मौसम में इस्तेमाल किए जाने लायक है। यह लक्ष्य का पीछा करने और उसे भेदने में सक्षम है।
3. अत्याधुनिक मिसाइल का यह एक विकासात्मक परीक्षण था, जो एक हवाई लक्ष्य को भेदने में सफल रहा। इस मिसाइल (क्यूआर - एसएएम) को रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) और अन्य प्रतिष्ठानों ने विकसित किया है।
4. इस हथियार प्रणाली के कुछ और दौर के परीक्षण इसी परीक्षण केंद्र से निकट भविष्य में होने की संभावना है।

चीता, चेतक की जगह लेने जा रहा है कामोव

भारतीय सेना में पुराने पड़ चुके चीता और चेतक हेलिकॉप्टर का स्थान लेने जा रहे **कामोव हेलिकॉप्टर** का निर्माण जल्द शुरू होने जा रहा है। **'मेक इन इंडिया' के इस अहम प्रॉजेक्ट के तहत** बेहद पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल की रूस यात्रा में बताया था कि **हेलिकॉप्टर के लिए संयुक्त प्रयास शुरू हो गया है।** भारत सरकार के कॉरपोरेट मंत्रालय ने पिछले महीने ही **इंडिया-रशिया हेलिकॉप्टर्स लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी है।** हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूसी कंपनियों के जॉइंट वेंचर में 2 इंजन वाले मल्टी-यूटिलिटी लाइट हेलिकॉप्टर कामोव बनेगा, जो ऊंचाई वाले इलाकों में काफी कारगर बताया गया है।

क्या है

1. **इस प्रॉजेक्ट के लिए हुए करार के मुताबिक 60 तैयार हेलिकॉप्टर रूस से आएंगे,** जबकि 40 को भारत में असेंबल किया जाएगा। बाकी बचे 100 हेलिकॉप्टर पूरी तरह से भारत में तैयार किए जाएंगे।
2. रूसी खेमे से संकेत मिले हैं कि **पहली डिलीवरी 2018 तक मिल सकती है।** डील के तहत सभी हेलिकॉप्टरों की सप्लाई 9 साल में पूरी होने की उम्मीद है।
3. पिछले साल अक्टूबर में डील के लिए बात बन गई थी, लेकिन इसमें देर हो गई। प्रॉजेक्ट पर करीब से नजर रखने वालों का कहना है कि रूस से आने वाले हेलिकॉप्टर भारत में बनने वाले हेलिकॉप्टरों से सस्ते बताए जा रहे थे, इसलिए बातचीत लंबी चली। हेलिकॉप्टर के वजन को लेकर भी कुछ समस्या थी, जिन्हें सुलझा लिया गया है।
4. **कामोव 3 दशकों से ज्यादा पुराने चीता और चेतक हेलिकॉप्टरों की जगह लेगा,** जिन पर सेना आज भी काफी हद तक निर्भर है।

5. ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में उड़ान के लिए कामयाब चीता हेलिकॉप्टरों को श्डेथ ट्रैप श भी कहा जा चुका है, क्योंकि सिंगल इंजन हेलिकॉप्टर होने के कारण इमर्जेंसी में इनके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना ज्यादा रहती है। आर्मी अफसरों का परिवार लंबे समय से चीता हेलिकॉप्टरों को फ्लीट से हटाने की मांग करता रहा है।
6. **ऑटो पायलट, मौसम रेडार, डेटा रिकॉर्डिंग और कंप्यूटराइज्ड इंजन वाले हेलिकॉप्टरों की मांग बढ़ी है।** भारत में अगले एक दशक में 600 लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टरों की सख्त जरूरत बताई गई है।
7. भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 187 लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर खुद बनाने की योजना है।

भारत ने डेंगू-मलेरिया का टीका बनाया

भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी का टीका तैयार कर लिया है। इसे जल्द बाजार में लाने की तैयारी है। मलेरिया के टीके के पहले चरण के मानवीय परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं, जबकि डेंगू के टीके के चूहों पर परीक्षण हुए हैं। दोनों टीकों के अगले चरण के परीक्षणों की तैयारी की जा रही है।

क्या है

1. भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि है कि दोनों टीकों ने पहला पड़ाव सफलतापूर्वक पार कर लिया है। **इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बॉयोटैक्नोलॉजी ने टीके तैयार किए हैं।**
2. मलेरिया एवं डेंगू मच्छरजनित बीमारियां हैं लेकिन मलेरिया एनाफिलीज तथा डेंगू एडीज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है।
3. 469 लोगों की मौत हुई थी देश में पिछले साल डेंगू और मलेरिया से
4. 10 लाख लोग मलेरिया और 1.11 लाख लोग डेंगू से ग्रस्त हुए थे वर्ष 2016 में
5. जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सीएसआईआर इन दो टीकों के अलावा चिकनगुनिया के टीके पर भी कार्य कर रहा है।

नाग का टेस्ट सफल

ऐंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) नाग का फ्लाइट टेस्ट सफल रहा है। टेस्ट मिशन में इसने लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इसका टेस्ट राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में किया गया। श्फायर ऐंड फॉरगेटश के नाग को कई अपग्रेडेड तकनीकों के साथ शामिल किया गया है।

क्या है

1. टॉप एटीजीएम नाग की क्षमता यूनीक बताई जाती है।
2. **इनमें इमेजिंग इन्फ्रारेड रेडार के साथ इंटिग्रेटिड एविऑनिक्स भी शामिल है।**
3. यह क्षमता दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। यह टेस्ट डीआरडीओ समेत कई रक्षा संगठनों के वैज्ञानिकों ने मिलकर किया।

पूरे देश में अब पेट्रोल-डीजल के दाम रोजाना तय होंगे

पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए जल्द आपको हर दिन नए दाम देने होंगे। किसी दिन तेल आपको कम कीमत पर मिलेगा, तो किसी दिन ज्यादा दाम देने पड़ेंगे। **सरकार 16 जून से पूरे देश में प्रतिदिन दाम तय करने की व्यवस्था लागू कर रही है।** सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां प्रतिदिन पेट्रोल-डीजल के दाम का समीक्षा करेंगी। **अभी तक कंपनियां 15 दिन में दामों की समीक्षा करती हैं।**

क्या है

1. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान के साथ बैठक के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी **इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 16 जून से प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बदलने का ऐलान किया।** तेल कंपनियों ने एक मई से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुडुचेरी, विशाखापट्नम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में यह योजना शुरु की थी।

2. इंडियन ऑयल का कहना है कि पेट्रोल-डीजल के प्रतिदिन दाम तय होने से बाजार की स्थिति का बेहतर ढ़ंग से पता चल सकेगा। इससे तंत्र में पारदर्शिता आएगी।
3. नई व्यवस्था से रिफाइनरी डिपो से पेट्रोल पम्पों तक सही ढंग से उत्पादों की पहुंच होगी। **कई विकसित देशों में पहले से दैनिक कीमत व्यवस्था पहले से लागू है।** उपभोक्ताओं को प्रतिदिन की कीमत के बारे में जानकारी देने के लिए कंपनियां मीडिया, पेट्रोल पंपों पर कीमत दर्शाना और एसएमएस के जरिए प्रतिदिन उपभोक्ताओं को जानकारी देना शामिल हैं।

पैन कार्ड से आधार लिंक पर लगी सुप्रीम कोर्ट की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट के मुताबिक जब तक **संवैधानिक पीठ** मामले को लेकर निर्णय नहीं ले लेती है, उस वक्त तक आधार कार्ड के पैन से लिंक के सरकारी आदेश पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि **पैन कार्ड से आधार के लिंक से अवैध होने वाले पैन कार्ड से कई दुष्परिणाम सामने आएंगे।** कोर्ट के मुताबिक फर्जी पैन एक अलग खतरा बना हुआ हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि संसद को इसके दुष्परिणामों को लेकर विचार करना चाहिए।

क्या है

1. कोर्ट के मुताबिक फर्जी **पैन की रोकथाम के लिए एस 139 एए में दंड प्रावधान आवश्यक है,** साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार को भरोसा दिलाना होगा कि आधार का डाटा लीक नहीं हो सकेगा।
2. कोर्ट ने उस दलील को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें पैन कार्ड से आधार के लिंक होने को स्वेच्छा का विषय कहा गया।
3. कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्हें आधार नहीं मिला हैं, वो भी सरकार के आदेश से प्रभावित होंगे।

जेआइटी के सामने पेश होने वाले पहले पाकिस्तानी पीएम

मुश्किलों में घिरे **पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हाईप्रोफाइल पनामा पेपर्स लीक मामले** की जांच कर रही समिति के समक्ष गुरुवार को पेश होंगे। भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर रही इस समिति के सामने पेश होने वाले वह देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। यह समिति पिछले महीने शरीफ के बेटों हुसैन और हसन से पूछताछ कर चुकी है।

क्या है

1. **संयुक्त जांच टीम (जेआइटी) के प्रमुख वाजिद जिया** ने लिखे पत्र में प्रधानमंत्री को मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों के साथ 15 जून को सुबह 11 बजे पेश होने के लिए कहा है।
2. 67 वर्षीय शरीफ को कजाखस्तान से लौटने के बाद समन भेजा गया था। शरीफ ने रविवार को लाहौर में अपने करीबियों के साथ इस मसले पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने जेआइटी के समक्ष पेश होने का निर्णय लिया।
3. सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री मरियम औरंगजेब के अनुसार प्रधानमंत्री को जेआइटी का समन मिला है और वह इसका सम्मान करते हुए इसके समक्ष पेश होंगे।
4. गौरतलब है कि शरीफ और उनके परिवार पर कथित मनी लांड्रिंग का पैसा विदेशी कंपनियों में लगाने का आरोप है। पिछले साल सामने आई पनामा के अवैध निवेशकों की सूची में शरीफ परिवार का नाम भी था। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पांच मई को छह सदस्यीय जेआइटी का गठन किया था।

अंतर्राष्ट्रीय

सऊदी, यूएई, मिस्र, बहरीन ने कतर से तोड़े रिश्ते

ब्रिटेन की राजनधानी में हुए आतंकी हमले के बाद आतंकवाद और इसका कथित तौर पर **समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ अन्य देशों के तेवर कड़े हो गए हैं। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात(यूएई) ने कतर**

से कई राजनयिक करार खत्म करने का फैसला किया है। एक ओर मिस्र ने कतर पर आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर यूएई का कहना है कि कतर पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र की सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है।

क्या है

1. **विश्व के ऐसे बहुत कम ऐसे देश हैं, जो आतंकवाद से अछूते हैं।** भारत और इसके पड़ोसी देश, तो आतंकवाद को दशकों से झेल रहे हैं।
2. ब्रिटेन की राजधानी लंदन के मध्य इलाके में छुरे लिए और नकली आत्मघाती जैकेट पहने तीन हमलावरों ने एक बाजार में हमला किया जिससे कम से कम सात व्यक्तियों की मौत हो गई और 48 लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आइएसआइएस ने ली है।
3. अब अपने देश में आतंकी गतिविधियों पर रोक के लिए **बहरीन, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब ने कतर से कई राजनयिक करार खत्म करने का फैसला लिया है।**
4. बहरीन ने सोकतर के साथ रिश्ते तोड़ने के अपने फैसले की जानकारी सार्वजनिक कर दी। आतंकवाद को बढ़ावा देने के अलावा बाहरीन ने कतर पर अपने आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने का भी आरोप लगाया है।
5. सऊदी के बेहद करीबी माने जाने वाले बहरीन ने आधिकारिक तौर पर कहा कि वो सभी हवाई और समुद्री करार कतर से खत्म करता है। इतना ही नहीं बहरीन ने कतर में ठहरे अपने नागरिकों को निर्देश दिए हैं कि 14 दिनों में वहां से लौट आएं।
6. सऊदी अरब ने भी राजनयिक रिश्ते, समुद्र, थल और हवाई करार कतर से सोमवार को खत्म कर दिए हैं। दोनों देशों ने कहा कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये अहम कदम उठाया गया है।
7. आतंकवाद से जूझ रहे सऊदी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इधर मिस्र और यूएई ने भी कतर के साथ सभी तरह के संबंध तोड़ने की घोषणा की है।

जापान ने सिविल एटमी डील को दी हरी झंडी

जापान की संसद ने भारत के साथ हुई **सिविल एटमी डील को मंजूरी दे दी है,** जिससे भारत को वहां से **एटमी मटीरियल और तकनीक पाने का रास्ता साफ होगा**। यह संधि अगले महीने से ही प्रभावी हो सकती है। **दुनिया में एटमी अटैक झेलने वाले एकमात्र देश जापान ने पहली बार किसी ऐसे देश के साथ न्यूक्लियर डील की है,** जिसने **परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए हैं।**

क्या है

1. **दोनों देशों को अब अपने अपने यहां न्यूक्लियर अथॉरिटी से जुड़े नियमों में संशोधन करना होगा।** संशोधन के दस्तावेजों के लेन-देन के बाद संधि प्रभावी हो जाएगी। वहां विपक्ष ने चिंता जताई थी कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं किए हैं तो परमाणु तकनीक का सैन्य इस्तेमाल हो सकता है। संधि में अलग से यह जोड़ा गया है कि अगर भारत ने एटमी टेस्ट पर रोक का 2008 का वादा तोड़ा तो वह डील रोक देगा।
2. **भारत को न्यूक्लियर मटीरियल रीप्रोसेस करने की इजाजत होगी,** लेकिन परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने की संभावना वाला एनरिच्ड यूरेनियम नहीं बना सकता। भारत को इंटरनैशनल अटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इन्स्पेक्शन के लिए तैयार रहना होगा।
3. **2010 में डील पर बात शुरू हुई थी और पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान डील के समझौते पर मुहर लगी थी।** इस अग्रीमेंट के तहत भारत में न्यूक्लियर पावर प्रॉजेक्टों का विकास किया जाएगा। इसके लिए भारतीय और जापानी कंपनियों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।
4. **भारत अब तक अमेरिका 11 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर चुका है।** न्यूक्लियर एनर्जी प्लांटों में सेफ्टी के लिहाज से जापान के इंतजामों को दुनिया में बेहतरीन माना जाता रहा है, लेकिन 2011 में फुकुशिमा में न्यूक्लियर प्लांट में हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए थे।

दक्षिण सागर में भारतीय सुनामी प्रणाली पर चीन नरम

दक्षिण चीन सागर में भारत और चीन के बीच तनाव कम होने के संकेत मिलने लगे हैं। क्षेत्र में भारत की उपस्थिति का कड़ा विरोध करने वाले चीन का दक्षिण सागर में भारतीय सुनामी चेतावनी प्रणाली पर सुर नरम पड़े हैं। बीजिंग ने नई दिल्ली के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

क्या है

1. **दक्षिण चीन सागर में चीन ने भी सुनामी प्रणाली लगाया है।** चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय प्रणाली मौजूदा तंत्र का हिस्सा हो सकती है। उनके मुताबिक, **सुनामी अर्ली वार्निंग रिसर्च क्षेत्र के सभी देशों के हितों के अनुकूल है।**
2. चीन और अन्य देश संयुक्त राष्ट्र की जरूरतों के अनुसार सुनामी प्रणाली स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में संबंधित देश मौजूदा तंत्र के तहत सहयोग बढ़ाने के मसले पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।
3. ज्ञात हो कि **वर्ष 2004 में आए विनाशकारी सुनामी के बाद भारत ने खुद की चेतावनी प्रणाली विकसित की है।** इससे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को सूचनाएं मुहैया कराई जाती हैं।
4. चीन दक्षिण चीन सागर के तकरीबन पूरे क्षेत्र पर अपना दावा ठोकता है। ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी इस क्षेत्र में अपना दावा करते हैं। चीन इस क्षेत्र में किसी भी देश के आगमन को हस्तक्षेप के तौर पर देखता है।
5. बीजिंग पूर्व में दक्षिण चीन सागर में भारत की मौजूदगी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अलग रहने की हिदायत दे चुका है। ऐसे में सुनामी प्रणाली पर चीन का रुख चौंकाने वाला है। इसे हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच बढ़ी कूटनीतिक पहल का परिणाम माना जा रहा है।

पनामा ने ताइवान से रिश्ते तोड़ चीन से संबंध जोड़े

पनामा ने वन चाइना पॉलिसी को मंजूर करते हुए ताइवान से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ चीन का हाथ थाम लिया है। इसे चीन के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। **इससे ताइपे व बीजिंग के बीच तनाव बढ़ सकता है।** पनामा का चीन से एक शताब्दी से भी ज्यादा समय से महज व्यापारिक संबंध था। पनामा के राष्ट्रपति जुआन कार्लोस वरेला ने टीवी पर दिए गए संदेश में नये कदम को देश के लिए सही रास्ता करार दिया। राष्ट्रपति ने कहा, **पनामा व चीन एक दूसरे को मान्यता देते हुए राजनयिक स्तर पर संबंध स्थापित कर रहे हैं।**

क्या है

1. **ताइवान चीन का अभिन्न हिस्सा है।** इस संबंध में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पनामाई समकक्ष इसाबेल सेंट के साथ बीजिंग में समझौते पर हस्ताक्षर किए।
2. **पनामा नहर से व्यापार करने वाला चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है।** उधर ताइवान के विदेश मंत्री डेविड ली ने पनामा के फैसले को खेदजनक बताया है।
3. ली ने कहा है कि चीन ने प्रलोभन देकर पनामा के ताइवान से रिश्ते खत्म करवाए। यह गंभीर मामला है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।
4. ताइवान पनामा को दी जाने वाली मदद को तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है। ज्ञात हो कि **ताइवान से कूटनीतिक रिश्ता रखने वाले देशों की संख्या नब्बे के दशक में करीब 30 थी।**
5. अब इस सूची में लैटिन अमेरिकी व प्रशांत क्षेत्र के कुछ छोटे देश ही रह गए हैं।

आर्थिक

जीएसटी काउंसिल ने लगाया कितना टैक्स

जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने पर सभी राज्य सहमत: 3 जून को हुई **जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को एक जुलाई से लागू करने पर सहमति जता दी है।** साथ ही काउंसिल ने इस बैठक में ट्रांजिशन प्रोविजन और रिटर्न से जुड़े दो अहम नियमों को मंजूरी दे दी है।

क्या है

1. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की इस बैठक में बिस्कुट, बीड़ी, फुटवेयर और रेडीमेड गारमेंट पर भी टैक्स की दरें तय कर दी गई हैं।
2. **500 रुपए से कम कीमत के फुटवेयर पर 5 फीसद** और 500 रुपए से ऊपर के फुटवेयर पर 18 फीसद का टैक्स लगेगा।
3. रेडिमेड गारमेंट पर 12 फीसद का टैक्स लगेगा।
4. कॉटन टैक्सटाइल पर 5 फीसद का टैक्स लगेगा।
5. सभी तरह के बिस्कुट पर 18 फीसद की दर से टैक्स लगेगा।
6. बीडी पर 28 फीसद की दर से टैक्स लगेगा, हालांकि इस पर सेस नहीं लगेगा।
7. इस मीटिंग के एजेंडे में सोना, टेक्सोटाइल्स और बिस्किट समेत छह कमोडिटी के टैक्स रेट पर विचार करना शामिल था। साथ ही इसमें शेष बची कमोडिटी के लिए सेस की दर भी तय की जानी थी।
8. **इससे पहले श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की 14वीं बैठक** में बिस्किट, टेक्सीटाइल, फुटवियर, बीड़ी, तेंदू पत्ताद के साथ ही साथ कीमती धातुओं, मोती, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थडर, सिक्कोंत और इमीटेशन ज्वैलरी पर टैक्सऔ रेट को टाल दिया था।

भारत-संयुक्त राष्ट्र कोष का शुभारंभ

भारत-यूएन विकास साझेदारी निधि की शुरुआत बेहद गरीब देशों की मदद के लिए शुरू की गई है। इस निधि का उद्देश्य **विश्व संगठन के सशक्त विकास लक्ष्यों (एसडीजी)** के तहत गरीबी कम करने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। एक मील के पत्थर **दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए इस निधि की शुरुआत हुई।**

क्या है

1. **इस फंड को दक्षिण-दक्षिण सहयोग (यूएनओएससी) के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।** फंड को कम विकसित देशों (एलडीसी) और लघु द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) पर ध्यान केंद्रित कर लगाया जाएगा।
2. निधि के शुभारंभ के मौके पर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और पूर्व पत्रकार एम जे अकबर ने कहा, श्हम आश्वस्त हैं कि यह साझेदारी हमारे समय की चुनौती को पूरा करेगी।श
3. वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि यह फंड प्रारंभिक योगदान के साथ शुरू हुआ है जो एक मिलियन डॉलर है।
4. यह पहली परियोजना, प्रशांत द्वीप देशों (सीईवीएसपीआईसी) में जलवायु प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए खर्च किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो जीटरस ने भारत के इस कदम का स्वागत किया।

वेतन श्रम संहिता को कैबिनेट की मंजूरी शीघ्र

सरकार ने चालीस से ज्यादा केंद्रीय श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में समेटने का काम पूरा कर लिया है। इनमें से वेतन संबंधी श्रम संहिता को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। **चार श्रम संहिताओं में पहली वेतन श्रम संहिता, दूसरी औद्योगिक संबंध श्रम संहिता, तीसरी सामाजिक सुरक्षा व कल्याण श्रम संहिता** तथा **चौथी व्यावसायिक सुरक्षा एवं कार्यदशाओं की श्रम संहिता है।** वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने इन सभी संहिताओं का अनुमोदन कर दिया है। शुरुआत के तौर पर श्रम संबंधी संहिता को शीघ्र ही स्वीकृति के लिए कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।

क्या है

1. सरकार के तीन वर्ष पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियां में **छह कानून** पारित कराए हैं। इनमें **बाल श्रम कानून, 2016, मातृत्व लाभ संशोधन कानून 2017, वेतन भुगतान संशोधन कानून 2017, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संशोधन कानून 2017, बोनस भुगतान संशोधन कानून 2015** के अलावा अधिसूचना के जरि ए संशोधित औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश कानून, 1946 शामिल हैं।

2. इसके अलावा गैर-कृषि श्रमिकों की दैनिक न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया जा चुका है। अब **इस न्यूनतम मजदूरी को 246 रुपये से बढ़ाकर श्सीश् एरिया में 350 रुपये, 'बी' एरिया में 437 रुपये** तथा **'ए' एरिया में 523 रुपये कर दी गई है।** एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल के जरिए नौ केंद्रीय कानूनों के साझा वार्षिक रिटर्न तथा ईपीएफओ और ईएसआइसी के साझा मासिक इलेक्ट्रानिक चालान-सह-रिटर्न कंप्यूटर पर भरे जा सकते हैं।
3. उन्होंने कहा कि 22 मई, 2017 तक 19,13,162 यूनिटों को यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (लिन) आवंटित किए जा चुके हैं। इसी तरह 2,95,423 लाख निर्धारित निरीक्षणों में से 2,76,931 को पूरा कर वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। 30 अप्रैल, 2017 से श्रम सुविधा पोर्टल पर ईपीएफओ तथा ईएसआइसी का साझा पंजीकरण शुरू हो गया है।
4. विभिन्न श्रम कानूनों के तहत मेंटेन किए जाने वाले 56 रजिस्टरों/फार्मो को पांच साझा रजिस्टरों/फार्मो में परिवर्तित कर दिया गया है। श्रम नियमों की संख्या भी अब 36 से घटाकर 12 कर दी गई है। ईपीएफ में 1.52 लाख प्रतिष्ठानों ने ओएलआरई पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया है।
5. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत अप्रैल, 2015 से न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित हो चुकी है। दावों के निपटान की अवधि को 20 रोज से घटाकर 10 रोज कर दिया गया है। आधार से संबद्ध ईपीएफ खातों से पैसा निकालने के लिए अब किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं। सेल्फ डिक्लेयरेशन काफी है।
6. ईएसआइ स्कीम में अब लक्षित औद्योगिक क्षेत्रों के बजाय पूरे जिले कवर होने लगे हैं। इसका दायरा सभी 393 जिलों तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है। पहले चरण में 301 जिले कवर कर लिए गए हैं। शेष जिलों को दूसरे चरण में लिया जाएगा।

कमोडिटी की ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कमोडिटी यानी जिंस वायदा कारोबार को विस्तार देने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी दे दी है। हालांकि उसने **कमोडिटी एक्सचेंजों को शुरू में सिर्फ एक कमोडिटी का ऑप्शन कांट्रेक्ट लांच करने की अनुमति दी है।** एक्सचेंजों को जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सेबी ने कड़ी पात्रता शर्तो का प्रावधान करते हुए कहा है कि एक्सचेंज पिछले 12 महीनों में टर्नओवर के लिहाज से शीर्ष पांच कमोडिटी में से किसी एक कमोडिटी के फ्यूचर कांट्रेक्ट का ऑप्शन लांच कर सकेंगे। **ऑप्शन के लिए तभी कमोडिटी के फ्यूचर कांट्रेक्ट को चुना जा सकेगा,** यदि पिछले एक साल के दौरान उसका दैनिक औसत **टर्नओवर एग्री कमोडिटी के मामले में कम से कम 200 करोड़ रुपये और नॉन एग्री कमोडिटी के मामले में 1000 करोड़ रुपये हो।**

क्या है

1. सेबी ने एक सकरुलर में कहा है कि **ऑप्शन कांट्रेक्ट में ट्रेडिंग शुरू करने के इच्छुक कमोडिटी एक्सचेंजों को इसकी लांचिंग से पहले अनुमति लेनी होगी।** एक्सचेंज लंबे अरसे से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने की अनुमति देने की मांग करते रहे हैं। हालांकि सेबी ने पिछले साल ही इसकी अनुमति दे दी थी लेकिन कुछ कानूनी जरूरतों के जरूरतों के चलते इस पर अमल टाल दिया गया।

क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग

1. ऑप्शन ट्रेडिंग कांट्रेक्ट खरीदने वाले ट्रेडर को कांट्रेक्ट के अंतिम दिन तक सौदा खरीदने या बेचने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उसे यह कांट्रेक्ट नामंजूर करने का भी अधिकार होगा। यानी कोई व्यापारी, किसान या कोई अन्य व्यक्ति को कमोडिटी के मूल्य में परिवर्तन होने पर फायदा लेने का अधिकार होगा और नुकसान होने पर उसे अस्वीकार भी कर सकेगा।
2. सौदा खरीदने वाले को इसके एवज में शुल्क अदा करना होगा। आसान शब्दों में कहें तो सरकार एमएसपी पर कृषि उपज खरीदने का विकल्प देकर एक तरह के मुफ्त में किसानों को ऑप्शन की सुविधा देती है।
3. वायदा कारोबार में सौदा खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को कांट्रेक्ट के अंतिम दिन तक सौदा या तो बाजार में प्रचलित मूल्य पर निपटाकर उसका फायदा या नुकसान अनिवार्य रूप से उठाना पड़ता है या फिर निपटान के दिन डिलीवरी के जरिये सौदा निपटाना पड़ता है।

2. सेबी ने गहन विचार विमर्श करने के बाद सीधे किसी कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग की अनुमति देने के बजाय कमोडिटी के फ्यूचर कांट्रेक्ट में ऑप्शन ट्रेडिंग की अनुमति दी है ताकि इससे जुड़े जोखिम को कम किया जा सके। कमोडिटी एक्सचेंजों में अभी तक सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग यानी वायदा कारोबार की अनुमति है।
3. सेबी ने ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोडक्ट तैयार करने और इससे जुड़े जोखिम प्रबंधन के लिए अनिवार्य गाइडलाइन तैयार की है। **एक्सचेंजों को इस गाइडलाइन का पालन करना होगा।** उसने ऑप्शन की ट्रेडिंग, निपटान अवधि और पोजीशन लिमिट के बारे में गाइडलाइन तैयार की है। सेबी ने यूरोपियन पद्धति के ऑप्शन की अनुमति दी है जिसके तहत सेटलमेंट कांट्रेक्ट के अंतिम दिन होगी।

कैबिनेट में किसानों के लिए बड़ा फैसला

मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब **किसानों को कर्ज के ब्याज पर ज्यादा छूट मिलेगी।** इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जो **एक साल में कर्ज को चुकाएंगे।** कैबिनेट की की बैठक में **ब्याज की दर तीन फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी कर दी गई है।**

क्या है

1. मोदी सरकार के इस फैसले के तहत **किसानों को कर्ज के ब्याज पर अब पहले के मुकाबले ज्यादा छूट मिलेगी। किसानों को तीन लाख तक के ऋण पर ब्याज में यह छूट मिलेगी।**
2. ब्याज में छूट **तीन फीसदी से बढ़ाकर पांच फीसदी किया गया है।** इसका फायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जो एक साल में ऋण चुकता करेंगे।
3. कैबिनेट के इस फैसले से केंद्र पर 19 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कैबिनेट ने इस वित्त वर्ष के लिए ब्याज पर सब्सिडी देने के लिए 20,339 करोड़ की मंजूरी भी दी।

वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **वित्तीय समाधान और जमा राशि बीमा विधेयक 2017** के पेश किए जाने के प्रस्ताव का अपनी मजबूरी दे दी है। इस विधेयक में **बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं में दिवालियापन की स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक समाधान से जुड़े प्रावधान उपलब्ध होंगे।** वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 के लागू होने पर एक समाधान निगम की स्थापना हेतु मार्ग प्रशस्त होगा। इससे इस विधेयक की अनुसूचियों में सूचीबद्ध क्षेत्रवार अधिनियम के समाधान संबंधी प्रावधानों को समाप्त करने अथवा संशोधित करने में मदद मिलेगी।

क्या है

1. इसके परिणामस्वरुप **जमा राशि बीमा और ऋण गारंटी निगम अधिनियम, 1961** को समाप्त करने से लेकर जमा राशि बीमा अधिकारों के स्थानांतरण और समाधान निगम के प्रति उत्तरदायित्व कायम करना भी संभव होगा।
2. समाधान निगम वित्तीय प्रणाली के स्थायित्व और दृढ़ता का संरक्षण करेगा और एक तर्कसंगत सीमा तक बाध्यताओं के दायरे में उपभोक्ताओं का संरक्षण करेगा तथा एक संभव सीमा तक लोगों के धन का भी संरक्षण करेगा।
3. सरकार ने हाल में **गैर वित्तीय संस्थाओं के तरलता समाधान के लिए तरलता और दिवालियापन संहिता, 2016 (कोड) को लागू किया है।** प्रस्तावित विधेयक वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समाधान कार्यक्रम प्रस्तुत करके कोड के प्रतिपूरक की भूमिका निभाता है। इसके लागू हो जाने पर कोड के साथ यह विधेयक अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक समाधान आधारित कार्यक्रम उपलब्ध करेगा।
4. **वित्तीय समाधान और जमाराशि बीमा विधेयक, 2017 का लक्ष्य वित्तीय तौर पर खस्ताहाल वित्तीय सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं को राहत देना है।** खस्ताहाल कारोबारों को बचाने के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को सीमित करके वित्तीय संकट के समय में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के बीच अनुशासन स्थापित करना भी इसका लक्ष्य है।
5. दूसरी ओर, संकट के समय आवश्यक औजार उपलब्ध कराकर, पर्याप्त रोकथाम के उपायों को सुनिश्चित करके अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थायित्व कायम रखने में मदद मिलेगी।

6. इस विधेयक का लक्ष्य बड़ी संख्या में खुदरा जमाकर्ताओं के लाभ के लिए जमाराशि बीमा के मौजूदा ढांचे को सशक्त और सुसंगत बनाना है। इसके अलावा, इस विधेयक के माध्यम से खस्ताहाल वित्तीय संस्थाओं की समस्याओं के निदान के लिए लगने वाले समय और धन में कमी लाना भी इसका लक्ष्य है।

विनिर्माण क्षेत्र में सब्सिडी के लिए और फंड

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को भारत में मैन्यूफैक्चरिंग करने को प्रोत्साहन देने के लिए **एक स्कीम मॉडीफाइड स्पेशल इनसेंटिव पैकेज स्कीम (एम-सिप्स) शुरू की थी।** इसके तहत **गैर एसईजेड क्षेत्रों में मैन्यूफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने के लिए 25 फीसद पूंजीगत सब्सिडी दी जा सकती है।** उद्योगों को सब्सिडी देने के लिए इस स्कीम के तहत 10 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया था। इस फंड के तहत देश के इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में 40-42 हजार करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया था।

क्या है

1. इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बीते दो वर्ष में निवेश की यह सीमा पार हो चुकी है। लिहाजा **सब्सिडी के लिए आवंटित फंड** भी समाप्त हो चुका है।
2. नई इकाइयों को सब्सिडी देने के लिए अब नए सिरे से फंड की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के सीईओ को नए सिरे से फंड का आकार तय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।
3. नीति आयोग की एक समिति को अब यह तय करना है कि भविष्य में देश के इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में कितने निवेश की संभावना है। सब्सिडी स्कीम में फंड का आकार इसके बाद ही तय हो पाएगा।
4. इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के मुताबिक देश में बीते **दो साल में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 72 कंपनियां मैन्यूफैक्चरिंग शुरू कर चुकी हैं।** इन में 42 मोबाइल कंपनियां है जबकि 30 कंपनियां कंपोनेंट निर्माण से जुड़ी हैं।
5. इनमें फॉक्सकॉन, फ्लैक्ट्रॉनिक्स और जाबिल जैसी विदेशी कंपनियां हैं तो लावा, इंटेक्स जैसी भारतीय कंपनियां भी हैं जो अभी तक चीन में मैन्यूफैक्चरिंग कर रही थीं। यह और बात है कि अब वापस भारत आकर मोबाइल हैंडसेट निर्माण कर रही हैं। इन सभी प्रयासों से देश के भीतर 1.65 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।
6. **इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक बीते दो साल में इस क्षेत्र में आने वाले निवेश में दस गुना की वृद्धि हुई है।**
7. 2014 में इस क्षेत्र में 13800 करोड़ रुपये का निवेश आया था। लेकिन 2016 में 126838 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता हो चुकी है।

रिटेल इंडेक्स में शीर्ष पर भारत

व्यापार सुगमता के पैमाने पर 30 विकासशील देशों में चीन को पछाड़ भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। एक अध्ययन में यह बात कही गई है। इसमें प्रमुख कारकों के रूप में **तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था,** एफडीआइ नियमों में नरमी और खपत के बढ़ने का उल्लेख किया गया है।

क्या है

1. **2017 ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (जीआरडीआइ) ने 16वें संस्करण में दुनियाभर में खुदरा निवेश के लिए टॉप 30 विकासशील देशों की रैंकिंग की है।** इसमें 25 मैक्रोइकोनॉमिक और रिटेल-विशेष वैरिएबल का विश्लेषण किया गया है। **रिपोर्ट का शीर्षक है-'द एज ऑफ फोकस'।**
2. जीआरडीआइ ने चीन को दूसरे पायदान पर रखा है। धीमी आर्थिक वृद्धि के बावजूद बाजार के आकार और रिटेल में निरंतर विकास के कारण अब भी खुदरा निवेश के लिए चीन सबसे आकर्षक बाजारों में से एक है।
3. मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म एटी केर्नी के अनुसार, यह अध्ययन अपने में खास है। इसमें न केवल उन बाजारों की पहचान की गई है जो आज सबसे ज्यादा आकर्षक हैं, बल्कि उनकी भी जो भविष्य में अवसर प्रदान कर सकते हैं।

4. **भारत का खुदरा क्षेत्र 20 फीसद की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।** बीते साल कुल बिक्री का आंकड़ा 1000 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। 2020 तक इस क्षेत्र का आकार बढ़कर दोगुना हो जाने की संभावना है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और बढ़ता मध्य वर्ग पूरे देश में खपत को प्रोत्साहित कर रहा है।

खादी धागा, गांधी टोपी और तिरंगे पर नहीं लगेगा टैक्स

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा पर कोई कर नहीं लगेगा। वहीं **नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा।** इसके अलावा जीएसटी परिषद ने पूजा के सामान के तहत बेचे जाने वाले रूद्राक्ष, खड़ाउ, पंचामत, तुलसी माला, पवित्र धागा और विभूति जैसे जिंसों को पूजी सामग्री के अंतर्गत रखने का फैसला किया और कहा कि जीएसटी के अंतर्गत इस पर छूट होगी। साथ ही चंदन टिका, बिना ब्रांड वाला शहद तथा दिया बत्ती को एक जुलाई से लागू होने वाली नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में छूट दी गई है। हालांकि पांच पूजी सामग्री **लोबहान, मिस्री, बताशा और बुरा पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।**

क्या है

1. **कपड़ा के मामले में 1000 रुपये से कम के कंबल, पर्दा, बिछावन, शौचालय और रसोई गैस** में इस्तेमाल होने वाले लिनेन, तौलिये पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। साथ ही 1000 रुपये से कम लागत वाले नैपकिन, मच्छरदानी, बोरी, थैला, लाइफ जैकेट पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। वहीं 1,000 रुपये से अधिक लागत वाली उक्त वस्तुओं पर 12 प्रतिशत कर लगेगा।
2. **रेशम और जूट धागा को छूट श्रेणी में रखा गया है** लेकिन कपास और प्राकृतिक फाइबर तथा अन्य सभी धागा पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। मानव निर्मित रेशम पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। खादी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के कपड़ों पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा गांधी टोपी तथा भारत के झंडे पर जीएसटी के तहत कर नहीं लगेगा।
3. **एक हजार रुपये तक की लागत वाले मानव निर्मित परिधान पर 5 प्रतिशत कर लगेगा जो मौजूदा 7 प्रतिशत से कम है।** जिनकी लागत 1000 रुपये से अधिक है, उन पर 12 प्रतिशत कर लगेगा। इके अलावा, माचिस, डिब्बाबंद जैविक उर्वरक पर नई व्यवस्था में 5 प्रतिशत कर लगेगा।
4. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ले लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं पर कर का निर्धारण कर दिया है। उन वस्तुओं पर 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत कर लगाया गया है। परिषद में जेटली के अलावा राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं।

प्रतिस्पर्धा में भारत की रैंकिंग गिरी

अमेरिका शीर्ष तीन रैंकिंग से बाहर हो गया है। जबकि **हांगकांग** ने अपनी रैंकिंग में लगातार दूसरे साल सुधार किया है। **स्विट्जरलैंड और सिंगापुर** क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। अमेरिका इसके बाद चौथे स्थान पर रहा। पिछले पांच साल में अमेरिकी के यह सबसे खराब रैंकिंग है। पिछले साल अमेरिका तीसरे स्थान पर था। नीदरलैंड ने इस सूची में पांचवां स्थान हासिल किया है। पिछले साल उसकी रैंकिंग आठवीं थी। शीर्ष 10 देशों में आयरलैंड छठे, डेनमार्क सातवें, लक्जमबर्ग आठवें, स्वीडन नौवें और यूएई दसवें स्थान पर रहा।

क्या है

1. जहां तक एशिया की बात है, **भारत की स्थिति गिरी है** अब 45वें स्थान पर आ गया है जबकि चीन सात पायदान के सुधार के साथ 18वें स्थान पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय कारोबार में उसके प्रयासों के कारण उसकी स्थिति सुधरी है।
2. सूची में निचले पायदान की बात की जाए तो इसमें वे देश शामिल हैं जहां राजनीति और आर्थिक उथल-पुथल देखी जा रही है। यूक्रेन 60वें, ब्राजील 61वें और वेनेजुएला 63वें स्थान पर रहे।
3. **आइएमडी वर्ल्ड कंपटीटिवनेस सेंटर स्विट्जरलैंड के आइएमडी बिजनेस स्कूल का रिसर्च ग्रुप है। वह 1989 से हर साल देशों की प्रतिस्पर्धा क्षमता पर रैंकिंग जारी करता है।**

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

4. इस साल की रैंकिंग में 63 देशों को शामिल किया गया है। साइप्रस और सऊदी अरब पहली बार इस सूची में आये हैं।
5. इस बीच आइएमडी वर्ल्ड कंपटीटिनेस सेंटर ने पहली बार डिजिटल कंपटीटिवनेस पर देशों की अलग से रैंकिंग की है। इस सूची में सिंगापुर सबसे ऊपर है।
6. इसके बाद स्वीडन, अमेरिका, फिनलैंड, डेनमार्क का स्थान आता है। निचले पायदान के पांच देशों में इंडोनेशिया, यूक्रेन, मंगोलिया, पेरू और वेनेजुएला शामिल हैं।

पहली बार खोजा गया 2 डी मैग्नेट

वैज्ञानिकों ने पहली बार टू-डी मैग्नेट (चुंबक) की खोज की है। यह एक परत वाले अणुओं से बना है। इस खोज से ज्यादा छोटी और प्रभावशाली डिवाइस के निर्माण की राह खुल सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार, चुंबकीय पदार्थ टेक्नोलाजी का बुनियाद तैयार करते हैं। इनका रोजमर्रा की जरूरतों मसलन **हार्ड डिस्क डाटा संग्रह** से लेकर सेंसर के कामों में अहम भूमिका होती है।

क्या है

1. **आकार में छोटी और तेज डिवाइसों के लिए** शोधकर्ता ऐसे नए **मैग्नेटिक मैटेरियल** की तलाश कर रहे हैं जो ज्यादा सटीक और प्रभावशाली हो।
2. अमेरिका के मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (एमआइटी) के शोधकर्ताओं ने **पहली बार 2डी दुनिया के मोनोलेयर या मैटेरियल्स में मैग्निटिज्म की खोज की है।**
3. ये मैटेरियल्स एक परत वाले अणुओं से बने होते हैं। इस शोध से जुड़े प्रोफेसर शीओडांग शू ने कहा कि हमारा ख्याल है कि नई सूचना प्रौद्योगिकी का उदय इन नए 2डी मैग्नेट पर आधारित हो सकता है।
4. वास्तव में मोनोलेयर मैटेरियल में खास गुण होते हैं। इस तरह की खासियत बहुपरत वाले मैटेरियल में दिखाई नहीं पड़ती है।

उद्योगों के लिए जीएसटी की कमेटियां गठित

टेलीकॉम, बैंकिंग और निर्यात जैसे क्षेत्रों की जीएसटी से जुड़ी चिंताएं दूर करने के लिए **जीएसटी काउंसिल ने अलग-अलग सेक्टरों के लिए 18 समूहों का गठन किया है।** ये समूह सभी उद्योग क्षेत्रों के साथ मिलकर उनकी चिंताओं का पता लगाएंगे और एक निश्चित समय सीमा के भीतर उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि अप्रत्यक्ष कर के नए ढांचे में प्रवेश में दिक्कत न हो।

क्या है

1. इन समूहों में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जा रहा है। **ये सभी समूह संबंधित उद्योग क्षेत्र की एसोसिएशनों व संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर दिक्कतों का पता लगाएंगे।** इतना ही नहीं ये समूह उद्योगों को अप्रत्यक्ष कर के नए ढांचे का हिस्सा बनने में मदद भी करेंगे।
2. वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक **सभी 18 समूहों का गठन इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है** ताकि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को इसमें शामिल किया जा सके।
3. अधिकारियों का चयन भी इसी लिहाज से किया गया है ताकि तय समय सीमा में उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके ताकि जीएसटी के लागू होने से पहले दूर किया जा सके।
4. जिन सेक्टरों के लिए समूहों का गठन किया गया है उनमें **आइटी, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, फूड प्रोसेसिंग, ई-कॉमर्स, तेल व गैस, फार्मा और एमएसएमई भी शामिल है।**
5. समूहों में शामिल अधिकारी इन उद्योगों की केवल जीएसटी से जुड़ी दिक्कतों पर ही विचार करेंगे। वित्त मंत्रालय का मानना है कि सरकार का यह प्रयास सभी उद्योग क्षेत्रों की जीएसटी से जुड़ी समस्याओं को समय रहते सुलझाने में मददगार साबित होगा।
6. काउंसिल ने 18-19 मई को श्रीनगर में हुई बैठक में इन समूहों के गठन का फैसला लिया था।

GST काउंसिल 16वीं बैठक

जीएसटी काउंसिल की 11 जून को हुई बैठक में **कई गुड्स पर टैक्स रेट्स को कम किया गया है। वित्त मंत्रालय को 133 सामानों (गुड्स) के जीएसटी रेट्स पर रिव्यू करने का प्रस्ताव मिला था,** जिसमें से **66 प्रोडक्ट पर टैक्स रेट को कम कर दिया गया है।** गौरतलब है कि जीएसटी के लागू होने से पहले यह काउंसिल की 16वीं बैठक है।

क्या कुछ हुआ सस्ता:

1. इस अहम बैठक में करीब **66 गुड्स (सामानों) पर टैक्स रेट को कम कर दिया गया है।** इसमें **इंसुलिन पर टैक्स रेट 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद** कर दी गई है।
2. वहीं **टोमैटो कैचअप, पैक्ड फूड्स और मसाले समेत कई प्रोडक्ट के टैक्स रेट को भी कम कर दिया गया हैं।**
3. साथ ही **75 लाख तक के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे से छूट दी गई है।** आपको बता दें कि पहले यह सीमा 50 लाख रुपए थी।
4. इस अहम बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने आज कई गुड्स पर टैक्स रेट कम करने का फैसला किया है। इससे आम आदमी के लिए कई सामान सस्ते हो जाएंगे।
5. हालांकि इससे सरकार के राजस्व पर जरूर असर होगा। उन्होंने कहा,''**जीएसटी काउंसिल ने कंपोजिशन की लिमिट 75 लाख कर दी गई है।** यानी, 50 लाख की बजाय अब 75 लाख के टर्नओवर वाला बिजनेस जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगा।
6. इसके तीन तरह के कारोबारियों को फायदा होगा। ट्रेडर एक फीसदी टैक्स देगा। वहीं, मैन्युफैक्चरर पर 2 फीसदी और होटल कारोबारियों पर 5 फीसदी टैक्स देकर जीएसटी के दायरे से बाहर रह सकते हैं।''

Esop और FDI पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स

आयकर विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए **ऐसे चुनिंदा इक्विटी इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले कैपिटल गेन से संबंधित टैक्स नियमों को स्पष्ट किया है,** जिन पर किसी भी तरह के **सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स** (एसटीटी) का भुगतान नहीं किया गया है। इससे ऐसे ट्रांजेक्शन को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता खत्म हो गई है जो बजट प्रपोजल के बाद शुरू हुई थी।

क्या है

1. आयकर विभाग ने कहा, "**आरबीआई, मार्केट रेग्युलेटर सेबी, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट और एनसीएलएटी की ओर से मान्यता प्राप्त** फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन (ईसॉप) और ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, भले ही उन पर कोई एसटीटी का भुगतान नहीं किया गया हो।"
2. **सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी)** की ओर से इस साल के बजट में कुछ रूल्स नोटीफाई किए गए थे, जो कहते थे कि अगर एसटीटी का भुगतान नहीं किया गया है तो ऑफ मार्केट लेनदेन में सूचीबद्ध शेयरों के अधिग्रहण पर पूंजीगत लाभ लगाया जाए, ऐसे में इसने वाजिब इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बड़ी राहत दी है।
3. गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में सरकार ने नोटिस किया था कि **धारा 10 (38) के दुरूपयोग किया जा रहा है** जो कि दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति का स्थानांतरण जैसे कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड से प्राप्त उस आय पर छूट प्रदान करती है जिस पर एसटीटी का भुगतान किया गया था।

विज्ञान और तकनीकी

वह जीन स्विच जिससे रुक जाएगा कैंसर का विकास

कैंसर के इलाज की दिशा में उम्मीद की नई किरण दिखी है। वैज्ञानिकों ने ऐसे **जीन स्विच की पहचान की है,** जिसकी मदद से **कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोका जा सकता है।** स्वीडिश के शोधकर्ताओं ने पाया कि **कैंसर कोशिकाएं और स्वस्थ कोशिकाएं अपने विकास के लिए अलग-अलग जीन स्विच का प्रयोग करती हैं।**

क्या है

1. शोधकर्ता जुसी ताइपेल ने कहा, **'सिद्धांत रूप से अगर हम केवल उस जीन स्विच को बंद कर दें,** जो कैंसर कोशिकाओं के विकास में सहायक है, तो कैंसर को रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया में स्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं होता।
2. इस खोज की मदद से **बेहद कम दुष्प्रभाव वाला कैंसर का कारगर इलाज संभव हो सकता है।** चूहे पर प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने कैंसर कोशिकाओं के विकास में सहायक जीन को हटाया।
3. इससे स्वस्थ कोशिकाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिला। स्वस्थ कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं के विकास के लिए जरूरी जीन के बिना ही अपनी गतिविधियों को जारी रखने में सक्षम होती हैं।
4. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसकी मदद से कैंसर के प्रकार के आधार पर विशेष दवाएं बनाने का रास्ता खुल सकता है।

कॉस्मिक किरणों से कैंसर का दोगुना खतरा

मंगल पर मानव भेजने की तैयारियों के बीच अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर बड़ा खतरा सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि **अंतरिक्ष में धरती का चुंबकीय कवच नहीं होता है।** अंतरिक्ष में लंबा समय बिताने वाले विभिन्न **आकाशीय किरणों (कॉस्मिक रे)** के संपर्क में आते हैं। इन किरणों के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को कैंसर होने का खतरा सामान्य से दोगुना हो जाता है।

क्या है

1. इस शोध को विज्ञान पत्रिका **साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित किया गया है।** पहले के अध्ययनों में भी कॉस्मिक किरणों के कारण कैंसर, मोतियाबिंद जैसी विभिन्न गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की बात सामने आ चुकी है।
2. **कॉस्मिक किरणों में आयरन और टाइटेनियम के परमाणु भी होते हैं।** ये अपने संपर्क में आने वाली कोशिकाओं को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं।
3. अमेरिका के लास वेगास स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा के शोधकर्ता फ्रांसिस ने कहा, श्मंगल अभियान 900 या इससे भी ज्यादा दिन का होगा। इस स्थिति में कॉस्मिक किरणों से बचाव के रास्ते तलाशने आवश्यक हैं।

बिना बिजली पीने लायक बन जाएगा गंदा पानी

केंद्र सरकार की ओर से अब तक 85 स्टार्टअप का चयन किया गया है, इसमें **बिहार और झारखंड से इकलौते गार्थ होल्लोवे और अमित कुमार का नाम शामिल है।** इन्होंने **इनोटेक एक्वा प्रोजेक्ट** की प्रस्तुति दी थी, जिसमें बिना बिजली या सौर ऊर्जा केगंदे पानी को साफ कर पीने लायक बनाया जा सकता है। इस पर **प्रति लीटर दो पैसा खर्च आएगा।** जानकारी बिहार उद्यमी संघ के अध्यक्ष कौशलेंद्र ने दी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की स्टार्टअप सूची में पहले से ही यह उत्पाद सूचीबद्ध है। अब भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से इसके लिए प्रमाणपत्र मिल चुका है।

क्या है

1. सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) के गार्थ ने कहा कि **बिहार में शुद्ध पेयजल न मिलना बड़ी समस्या है।** अधिकांश जिलों में **आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, बैक्टीरिया युक्त पानी है।** इसलिए बिहार में काम शुरू किया। टीम में कुल चार लोग हैं। इस उत्पाद से बिहार की एक बड़ी समस्या का निदान होगा क्योंकि यह **20 लीटर क्षमता से एक लाख लीटर तक की क्षमता में उपलब्ध है।** छोटे सिस्टम में एक 20 लीटर का जार, एक पंप और एक बैक्टीरिया फिल्टर है। इसके अलावा केमिकल का पाउच भी है। इसी के बूते गंदा पानी साफ हो जाता है। इसके बड़े उपकरण को पानी की टंकी से भी जोड़ा जा सकता है।
2. दो पैसे प्रति लीटर खर्च में पानी शुद्ध हो जाएगा। **बिहार सरकार का पीएचईडी विभाग इसे परख चुका है।** बिजली विभाग से चार उपकरण लगाने का ऑर्डर भी मिला है।
3. प्रतिदिन तीन हजार लीटर पानी को इसके जरिये शुद्ध किया जा सकता है। दस हजार लीटर के बाद केमिकल को बदलना पड़ेगा और एक लाख लीटर के बाद बैक्टीरिया फिल्टर को चेंज कर देना चाहिए।

देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन

महाराष्ट्र के नागपुर में देश के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, शुरूआत में यहां **चार चार्जिंग** स्टेशन लगाए गए हैं, हर एक स्टेशन की क्षमता अलग-अलग साइज और शेप के 200 वाहनों को चार्ज करने की है, इन स्टेशन पर फास्ट चार्जिंग के लिए सुपर चार्जर और बैटरी स्वेपिंग यूनिट भी लगाई गई हैं। चार्जिंग के लिए रेग्यूलर इलेक्ट्रिसिटी के अलावा सोलर पैनल भी लगाए गए हैं।

क्या है

1. **नागपुर में चलने वाले इलेक्ट्रिक टैक्सी बेड़े में कुल 200 इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल किया गया है,** इन में 100 महिन्द्रा ई2ओ प्लस कारें शामिल हैं, ई2ओ प्लस को सुपर चार्जर से 1 घंटा 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है, फुल चार्ज होने में 37 यूनिट बिजली लगेगी, इसकी लागत 6 रूपए प्रति यूनिट आती है ऐसे में 37 यूनिट पर करीब 225 रूपए का खर्चा आएगा।
2. फुल चार्ज होने के बाद महिन्द्रा ई2ओ प्लस 110 किमी का सफर तय करेगी, यह **3 किमी प्रति यूनिट का माइलेज देगी,** इस तरह इसका ड्राइविंग खर्च 2 रूपए प्रति किलोमीटर आएगा, यह खर्चा डीजल और पेट्रोल दोनों ही कारों की तुलना में कम है, यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि इस मामले में यह कुछ टू-व्हीलरों से भी बेहतर है।
3. **ई2ओ प्लस के अलावा इलेक्ट्रिक टैक्सी बेड़े में ई-रिक्शा को भी शामिल किया गया है।** इनके अलावा इलेक्ट्रिक बसों और ई-ऑटो का फिलहाल ट्रायल चल रहा है, उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें भी इलेक्ट्रिक वाहनों के बेड़े में शामिल किया जाएगा।
4. **ई2ओ प्लस की तरह इलेक्ट्रिक बसों और ई-ऑटो के लिए भी फास्ट चार्जर का इस्तेमाल होगा,** ई-रिक्शा के लिए यहां डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने के बजाए बैटरी बदलने की सुविधा मिलेगी, एक फुल बैटरी से ई-रिक्शा करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इनकी बैटरी को चार्ज होने में करीब 3 घंटे लगते हैं।

400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर दिखे जीवन के लक्षण

वैज्ञानिकों ने धरती से 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक तारे के आसपास जीवन के संकेत खोजे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी मदद से यह समझना आसान होगा कि धरती पर जीवन का विकास कैसे हुआ। वैज्ञानिकों ने बताया कि **पहली बार किसी बौने तारे के निकट प्रीबायोटिक (जीवन के विकास से पहले के) अणु मिले हैं।** ऐसे ही अणुओं से हमारा सौर मंडल बना था।

क्या है

1. वैज्ञानिकों ने **एक से अधिक तारों की इस व्यवस्था आइआरएएस 16293-2422** में इस विशेष अणु **मिथाइल आयसोसाइनेट** की पहचान की है।
2. नीदरलैंड की लीडन वेधशाला के वैज्ञानिक नील्स लिगटे "रक ने कहा, श्कार्बनिक अणुओं की यह श्रेणी **पेप्टाइड और अमीनो अम्लों के निर्माण में भूमिका निभाती है।**
3. **पेप्टाइड और अमीनो अम्ल ही प्रोटीन के रूप में जीवन का आधार बनते हैं।** 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित आइआरएएस 16293-2422 कई नए बने तारों की व्यवस्था है।
4. इसके आसपास मिथाइल आयसोसाइनेट गैस के अणुओं का मिलना केवल उसकी विकास व्यवस्था को समझने में ही नहीं, बल्कि हमारे सौर मंडल के विकास को समझने में भी सहायक है।
5. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि करीब 4.5 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल भी इसी तरह निर्मित हुआ था।

धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश

धरती के अलावा कहां पर जीवन है इसकी खोज वर्षों से लगातार जारी है। वैज्ञानिक लगातार इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि **नासा द्वारा खोजे गए सात नए ग्रहों में से तीन पर समुद्र होने की भी बात कही गई है।** तीन नए ग्रहों के बारे में यह संभावना जताई जा रही है कि वहां पर जीवन हो सकता है। दरअसल, **जीवन को लेकर सबसे बड़ी चीज वहां पर ऑक्सीजन और पानी की मौजूदगी है।** यदि यह संभावना हकीकत में बदलती है तो यह विज्ञान के लिए एक बड़ी खोज

जरूर साबित होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंगल पर भी कभी पानी हुआ करता था। नासा ने **इन नए ग्रहों की खोज स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए की है।**

क्या है

1. इसके अलावा **नासा के वैज्ञानिकों ने धरती से लगभग 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी स्थित** एक नए ग्रह की खोज की है जिसका **नाम केपलर-62** एफ है। संभावना जताई जा रही है कि यहां पर जीवन हो सकता है। इसकी वजह है कि इस ग्रह और पृथ्वी के बीच काफी कुछ समानताएं हैं, जिसके चलते वैज्ञानिकों ने इस तरह की संभावना जताई है। यह धरती से करीब 40 गुणा बड़ा है। यह लायरा तारामंडल की दिशा में है और यह उन ग्रहों की रेंज में है जो पथरीले होते हैं और जिन पर समुद्र होने की भी संभावना होती है।
2. 2013 में खोजा गया यह ग्रह हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे तारे की परिक्रमा कर रहे पांच ग्रहों में सबसे बाहर स्थित था। यहां पर जीवन की संभावनाएं जताने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि **इस ग्रह पर कई वायुमंडलीय सरंचनाएं हैं** जो इसे उतना गर्म बनाती हैं जोकि वहां सतह पर तरल पानी होने के जरूरी होता है। जिससे इस ग्रह पर जीवन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
3. इस ग्रह की खोज करने वाले अनुसंधानकताओं के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड धरती का 0.04 फीसदी वातावरण बनाता है। यहां पर कार्बन डाइआक्साइट इतनी ही है जितनी की पृथ्वी पर है। **इसकी कई परिस्थितियां ऐसी हैं जो इसको ग्रह मानने पर बाध्य करती हैं।** वर्ष भर रहने योग्य बनने के लिए इस ग्रह को एक ऐसे वातावरण की जरूरत होगी जोकि धरती से तीन से पांच गुना तक ज्यादा मोटा हो और पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड से बना हो। इस ग्रह पर इतनी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का होना इसकी तारे से दूरी पर निर्भर करता है। ऐसे में वातावरण में गैस का निर्माण हो सकता है क्योंकि ग्रह को गर्म तापमान घट जाता है। ये सात ग्रह छोटे स्टार **ट्रैपिस्ट-1** का चक्कर लगाते हैं। इनमें से छह ग्रहों का तापमान शून्य से 100 डिग्री सेल्सियस तक है।
4. ये ग्रह अपने सूरज यानी **ट्रैपिस्ट-1 का चक्कर 4, 6 और 9 दिन में पूरा करते हैं।** हालांकि यह पृथ्वी से 39 प्रकाश वर्ष (378 लाख करोड़ किमी) की दूरी पर हैं। जिस तारे का यह चक्कर लगाते हैं वह वह ज्यूपिटर ग्रह से थोड़ा ही बड़ा है।
5. इसकी रोशनी सूरज से 200 गुना कम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का असतित्व तभी तक है जब तक सूर्य है। यदि सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी भी नहीं बचेगी। लेकिन यह ग्रह मौजूद रहेगा। ट्रैपिस्ट में हाइड्रोजन गैस काफी धीमे जल रही है। यानी यह ब्रह्मांड की मौजूदा उम्र से 700 गुना ज्यादा चलेगा।

विटामिन ए की कमी से बढ़ता टीबी का खतरा

क्षय रोग यानी टीबी को लेकर चौंकाने वाला शोध सामने आया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि **जिन लोगों में विटामिन ए का स्तर कम होता है, उनमें टीबी होने की आशंका 10 गुना तक बढ़ जाती है।** टीबी दुनियाभर में असमय मौतों की बड़ी वजह है।

क्या है

1. **इस संबंध में अमेरिका स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी** के वैज्ञानिकों ने शोध किया। शोधकर्ताओं ने बताया कि **प्रति लीटर खून में विटामिन ए का स्तर 200 माइक्रो ग्राम से कम होने से टीबी का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है।**
2. प्रोफेसर मेगन मुर्रे ने कहा, शपिछले कुछ वर्षो में हुए अध्ययन में इसे सबसे बड़ा खतरा पाया गया है। अगर क्लीनिकल परीक्षण के दौरान विटामिन ए सप्लीमेंट और टीबी से बचाव के बीच संबंध प्रमाणित हुआ तो यह बड़ी उपलब्धि होगी।
3. बीमारी के मुहाने पर खड़े लोगों को बचाने में यह बेहद कारगर हो सकता है। **शोध के दौरान 6,000 ऐसे लोगों को शामिल किया गया,** जो टीबी मरीजों के संपर्क में थे।

4. शोध के दौरान इनमें से 192 लोग टीबी से ग्रसित हो गए। जांच में इन सबके शरीर में विटामिन ए की कमी पाई गई। 10 से 19 साल के लोगों में यह खतरा 20 गुना तक ज्यादा पाया गया।

धरती से 138 प्रकाश वर्ष दूर मिले दो विशाल ग्रह

खगोलविदों ने दो नए विशाल गैसीय ग्रहों की खोज की है। ये हमारी धरती से 138 प्रकाश वर्ष दूर हैं और एक तारे की परिक्रमा करते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार, **इनमें से एक का द्रव्यमान शनि ग्रह जितना है,** जबकि दूसरा ठंडा ग्रह है। इसका द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह से कई गुना ज्यादा है।

क्या है

1. **ये दोनों ग्रह एचडी 27849 नामक तारे की परिक्रमा करते हैं।** इस तारे की पहचान 2005 में हुई थी और इसका द्रव्यमान सूर्य की अपेक्षा 20 फीसद कम है।
2. जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनामी के ट्राईफोन ट्राईफोनोव के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने एचडी 27849 सिस्टम में मौजूद नए ग्रहों की खोज के लिए नए आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने दो नए गैसीय ग्रहों की पहचान की।
3. **इन्हें एचडी 27894 सी और एचडी 27894 डी नाम दिया गया है।** एचडी 27894 सी का द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह 0.16 गुना ज्यादा है। इस ग्रह को अपने तारे की परिक्रमा करने में महज 36 दिन का वक्त लगता है।
4. यह अपने तारे की परिक्रमा काफी करीब से करता है। जबकि एचडी 27894 डी का द्रव्यमान बृहस्पति ग्रह से 5.4 गुना ज्यादा है। इसे अपने तारे की परिक्रमा करने में 14 साल से ज्यादा का समय लगता है। यह अपने तारे से काफी दूर स्थित है।

विविध

विश्व का सबसे बड़ा विमान दुनिया के सामने

अमेरिका में 1 जून को **दुनिया के सबसे बड़े विमान 'स्ट्राटोलांच' की पहली झलक मिली।** कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित हैंगर से पहली बार विमान को बाहर निकाला गया। अब विमान ईंधन और उड़ान की जांच के लिए पूरी तरह तैयार है। **यह विशाल विमान सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लांच करने के लिए बनाया गया है।** मौजूदा तकनीक में रॉकेट सैटेलाइट लांच करते हैं, लेकिन यह विमान स्ट्राटोलांच धरती की निचली कक्षा तक उड़ान भरकर वहां सैटेलाइट को छोड़ आएगा। फिर आसानी से उड़ान भरकर यह धरती पर लौट आएगा। **यह तकनीक रॉकेट की तुलना में काफी सस्ती पड़ेगी।** भविष्य में इस विमान से इंसानों को भी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है।

क्या है

1. **स्ट्राटोलांच दरअसल दो जुड़वां विमानों को जोड़कर बनाया गया है।** इसमें दो कॉकपीट हैं। इन दो विमानों के बीच में ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाला रॉकेट लगा होगा।
2. **माइक्रोसॉफ्ट के सहसंस्थापक पॉल एलेन ने यह विमान बनाने की कल्पना की थी।** 2011 में उन्होंने स्ट्रैटोलांच नाम से कंपनी बनाकर काम शुरू कर दिया।
3. स्ट्रैटोलांच के सीईओ जेन फ्लोड के मुताबिक 2019 तक विमान को लांच कर दिया जाएगा।

रोचक तथ्य:

1. फुटबाल पिच के बराबर पंख
2. 385 फुट लंबे हैं विमान के पंख
3. 6 इंजन हैं इसमें बोइंग 747 के
4. 50 फीट है इसकी ऊंचाई
5. 28 पहिए लगे हैं इसमें
6. 226,796 किलोग्राम वजन ढोने में सक्षम
7. 300 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट की शुरुआती कीमत

भारतवंशी आयरलैंड का पीएम

भारतवंशी लिओ वराडकर आयरलैंड का पीएम बन इतिहास रचे हैं। वो अभी सिर्फ 38 साल के हैं और आयरलैंड के प्रधानंत्री बने हैं। लिओ वारडकर की बहन शुबाधा वराडकर जो एक ओडिशी डांसर भी हैं उन्होंने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते हैं जिसने साल 1960 में अपनी दुनिया मुंबई से आयरलैंड में बसाई थी।

क्या है

1. **लिओ के पिता एक डॉक्टर हैं** और आयलैंड की नर्स मरियम से शादी थी। लिओ खुद एक डॉक्टर हैं। उनके माता-पिता मुंबई आते रहते हैं और अपने पुस्तैनी गांव भी जाते हैं। लियो ने अपनी इंटर्नशिप केईएम से की है।
2. **38 साल के लिओ वराडकर एक डॉक्टर हैं** और एक डॉक्टर मैथ्यू बैरट के साथ रिलेशनशिप में हैं। लिओ पीएम बन जाते हैं तो आयरलैंड चौथा देश होगा जिसका राष्ट्राध्यक्ष खुले तौर पर गे होगा।
3. इस मामले पर उनकी कजन का कहना है कि लिओ बोल्ड और ईमानदार हैं। उन्होंने इरिश मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा भी है कि वो एक गे हैं। आयरलैंड में गे शादियों को कानूनी अधिकार मिला हुआ है।
4. आपको बता दें कि इससे पहले बेल्जियम, आइसलैंड और लक्जमबर्ग के राष्ट्राध्यक्ष गे हैं।

भारतवंशी बनीं नेशनल स्पेलिंग बी विजेता

कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो की रहने वाली अनन्या ने 12 घंटे की प्रतिस्पर्धा और 35 शब्दों का सही उच्चारण कर प्रतियोगिता में जीत हासिल की। ओकलाहोमा के रहने वाले भारतीय मूल के 14 वर्षीय रोहन राजीव दूसरे स्थान पर रहे। वह अंतिम दौर में समुद्र तट पर पाई जाने वाली घास 'मैरम' का सही उच्चारण करने में चूक गए। अनन्या ने जीत के साथ इस प्रतियोगिता में भारतीयों के दबदबे को कायम रखा है। **छठी कक्षा की छात्रा अनन्या** ने ट्राफी लेने के बाद कहा, यह सपने के सच होने जैसा है। **1925 से चल रही स्पेलिंग बी प्रतियोगिता में भारतीयों ने पिछले दस साल से अपना दबदबा बनाए रखा है।** उन्होंने पिछले 17 साल में 14वीं बार इस प्रतियोगिता को जीता है। भारतवंशी छात्रों ने 2014, 2015 और 2016 में संयुक्त विजेता बनकर रिकार्ड बनाया था।

रूस ने किया आधुनिक मिसाइल का परीक्षण

रूस ने अपनी अब तक की सबसे आधुनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। करीब 4600 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली इस मिसाइल पर पिछले कई वर्षों से काम चल रहा था।

क्या है

1. **इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 30 जुलाई 2016 को व्लादिवोस्तोक पोर्ट से किया गया था,** तब इसकी स्पीड 3800 प्रति घंटा थी। तभी से इसकी रफ्तार बढ़ाने पर काम जारी है।
2. 'जिरकॉन' नामक इस हाइपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल की रूसी नौसेना ने तस्वीरें जारी की हैं। इसकी रफ्तार 3,800 से 4600 किमी प्रति घंटे है। यानी की आवाज से 5 गुना ज्यादा है।
3. रूस का दावा है कि कोई भी मिसाइल रोधी प्रणाली इस मिसाइल को रोक नहीं सकता। अगर यह रडार की पकड़ में आ भी गई तो दुश्मन के संभलने से पहले ही उस पर धावा बोल देगी। इसे वर्ष 2018 तक नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा।

निरुपमा राव को अमेरिकी थिंक टैंक में अहम जिम्मेदारी

अमेरिका में भारत की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव को एक शीर्ष अमेरिकी संस्था में नीतिगत मामलों का सहयोगी नियुक्त किया गया है। **चीन में भारत की राजदूत रहीं 66 वर्षीय राव** इस समय चीन-भारत समझौते के की एक परियोजना में अमेरिका में कार्य रही हैं।

क्या है

1. इस परियोजना के तहत वह एक किताब तैयार कर रही हैं। **राव विल्सन सेंटर एशिया प्रोग्राम से जुड़ेंगी** और वह तीन महीने तक विल्सन सेंटर में रहकर वैश्विक मुद्दों पर संस्था की नीति को अंतिम रूप देंगी।
2. उनका कार्य खासतौर पर भारत पर केंद्रित होगा। उनका यह कार्य जून से शुरू होगा। **निरुपमा राव भारत में विदेश मंत्रालय की पहली महिला प्रवक्ता रही हैं।**

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

3. विदेश सचिव के रूप में उन्होंने वर्ष 2009 से 2011 तक कार्य किया।

RERA आने के बाद बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम

उपभोक्ताओं के अधिकार की सुरक्षा और पारदर्शिता लाने के वादे के साथ **बहुत-प्रतीक्षित रियल एस्टेट अधिनियम रेरा (RERA) 1 मई 2017 से लागू हो गया है।** हालांकि **अब तक केवल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इन नियमों को अधिसूचित किया है।** माना जा रहा है कि यह नियम यह अतीत में अचल संपत्ति क्षेत्र में देखी गई अस्थिरता को कम करने के साथ ही यह बिल्डर और बॉयर्स के बीच विश्वास की कमी को खत्म भी कोशिश करेगा। हालांकि **रेरा के पूर्ण रूप से अमल में आने के बाद आवासीय कीमतें बढ़ने की संभावना है।** इसके कुछ प्रमुख कारण भी हैं..

1. **सप्लाई हो जाएगी कमः** - **रेरा अचल संपत्ति उद्योग में मांग और आपूर्ति के आर्थिक ढांचे को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।** सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी क्योंकि बिल्डर सिर्फ उन्ही प्रोजक्ट को लॉन्च करेंगे जिन्हें वो दिए हुए समय में पूरा कर पाएंगे।
2. **डिमांड रहेगी तेजः** - हालांकि रेरा के आने के बाद डिमांड लगातार मजबूत बनी रहेगी। लेकिन इसमें **रीडिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति देखने को मिलेगी।** जैसा कि आवासीय निवेश पर जोखिम कम हो सकता है उसी तरह इसका रिवार्ड भी घट जाएगा। इससे होगा यह कि ज्यादा जोखिम और ज्यादा रिटर्न पाने की सोच रखने वाले निवेशकों की संख्या में भी कमी देखने को मिलेगी। हम निवेशकों का मनोबल टूटने की स्थिति को भी देख सकते हैं क्योंकि सेल्स में तेज इजाफे के कारण कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। यह एक अजीब सी स्थिति होगी जिसे अब तक नहीं देखा गया।
3. **डेवलपर की लागतः** - **अगर डिमांड और सप्लाई के इतर बात करें तो डेवलपर की होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी।** अनिवार्य रूप से, सभी मंजूरी मिलने के बाद ही कोई नई परियोजनाएं लॉन्च की जा सकेगी। 'प्री-लॉन्च' और 'ऑफिशियल लॉन्च' के बीच मूल्य वृद्धि का मौका जो कि पहले डेवलपर्स के पास उपलब्ध था वह अब नहीं है।
4. **जमीन की कीमतेंः** - **नोटबंदी के बाद जमीन की कीमतें शहर भर के भीतर ही बढ़ेंगी।** भूमि की खरीद पर अन्य व्यवसायों के माध्यम से अतिरिक्त कैश जुटाने की छूट नहीं होगी। रेरा के आने के बाद डेवलपर के सामने यह भी बाध्यता रहेगी कि वो भूमि की खरीद के लिए लीगल मनी का ही इस्तेमाल करे। यह डेवलपर की ओवरऑल इनपुट कॉस्ट में इजाफा करेगा और इसी के कारण उसके प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ जाएंगी।

नासा के अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया भारतवंशी

नासा ने अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतवंशी लेफ्टिनेंट कर्नल राजा ग्रिंडर चारी समेत 12 नए अंतरिक्षयात्रियों को चुना है। इन्हें धरती की कक्षा और अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इनका चयन रिकार्ड 18300 आवेदकों में से किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से चुने गए **अंतरिक्षयात्रियों में सात पुरुष और पांच महिलाएं हैं।** नासा ने पिछले दो दशक में यह सबसे बड़ा समूह चयनित किया है। दो साल के प्रशिक्षण के बाद नए अंतरिक्षयात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शोध और नासा के नए ओरियन स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जा सकता है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और नासा के कार्यकारी प्रशासक राबर्ट लाइटफूट ने ह्यूस्टन में स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में इनके नाम की घोषणा की।

क्या है

1. चुने गए अंतरिक्षयात्रियों में **छह सैन्य अधिकारी, तीन वैज्ञानिक, दो डॉक्टर और एक स्पेसएक्स का इंजीनियर है।** नए अंतरिक्षयात्री के तौर पर चुने गए 39 वर्षीय चारी 461वें फ्लाइट टेस्ट स्क्वाड्रन के कमांडर और कैलिफोर्निया में स्थित एडवर्ड एयरफोर्स बेस के एफ-35 इंटीग्रेटेड टेस्ट फोर्स के निदेशक भी हैं। वह आयोवा के वाटरलू में रहते हैं।
2. उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल से की और एमआइटी से एयरोनॉटिक्स में मास्टर की डिग्री ली है। उनके पिता श्रीनिवास चारी हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग करने के बाद अमेरिका में जाकर बस गए थे।

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)** 7463950774, **(DIBRUGARH)** 7086708270, **www.ksgindia.com**

4जी कनेक्टिविटी में भारत विश्व में 15वें स्थान पर

अपनी शुरुआत के प्रथम छह महीनों में 10 करोड़ ग्राहकों को आकर्षित करने वाले जियो ने **भारत को विश्व में 4जी उपलब्धता के मामले में 15वें स्थान पर पहुंचा दिया है।** लंदन की **वायरलेस कवरेज मैपिंग कंपनी ओपनसिग्नल द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।** ओपनसिग्नल की 'स्टेट ऑफ एलटीइ' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 2016 की तीसरी तिमाही में 4जी उपलब्धता 71.6 प्रतिशत थी, जो अब 2017 की पहली तिमाही में उछाल के साथ 81.6 प्रतिशत पर आ गई है।

क्या है

1. ओपनसिग्नल के सह-संस्थापक और सीईओ ब्रेंडन गिल ने एक बयान में कहा, '**भारत बहुत ही अद्भुत और तेजी से बदलता मोबाइल बाजार है।** यहां की सरकार और अन्य हितधारकों को लगातार अत्यधिक अवसरों को सुनिश्चित करना और विश्व सूची में सभी मानकों पर ऊंचाई पर पहुंचना होगा, ताकि उच्च तीव्रता की गुणवत्ता और अपने 10 लाख से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए सुसंगत मोबाइल संबंधी अनुभव सुनिश्चित किए जा सकें।'
2. **जब बात 4जी डाउनलोड स्पीड (गति) की आती है तो भारत पीछे है।** भारत में 4जी डाउनलोड की औसत स्पीड 5.1 मेगाबाईट प्रति सेकेंड(एमबीपीएस) है।
3. अध्ययन बताता है, 'यह 4जी डाउनलोड स्पीड विश्व में औसतन 3जी डाउनलोड स्पीड से मामूली स्तर पर अधिक है, जोकि 4.4 एमबीपीएस है।' जियो के अलावा भारतीय बाजार में अन्य सेवा प्रदाताओं की उपलब्धता का स्तर 60 प्रतिशत के आसपास है।
4. **4 जी उपलब्धता के मामले में दक्षिण कोरिया ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किया है** और इस परीक्षण में 4 जी डाउनलोड स्पीड मामले में वह दूसरा सबसे ज्यादा स्पीड वाला देश है।
5. अपनी इस रिपोर्ट के लिए ओपनसिग्नल ने 75 देशों को शामिल करते हुए, सामान्य उपयोग के लिए रोजाना स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं से यह आंकड़े जुटाए थे।
6. नई एलटीइ नेटवर्क के साथ कई देशों की 4जी उपलब्धता सीमित हो सकती है, लेकिन अपने लाईट लोड्स (प्रकाश भार) के कारण संभावित तीव्र स्पीड को प्राप्त कर सकते हैं।'

डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री, **जे. पी. नड्डा को विश्व स्वास्थ्य संगठन- डब्ल्यूएचओ महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।** श्री जे. पी. नड्डा को यह सम्मान **'सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए डब्ल्यूएचओ के तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कनवेंशन (एफसीटीसी) के क्रियान्वयन** में तेजी लाने हेतु राष्ट्रीय परामर्श' कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्वी एशिया की क्षेत्रीय निदेशक, डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह ने दिया। इस अवसर पर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और श्रीमती अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित थीं।

क्या है

1. श्री नड्डा ने कहा कि **भारत ने तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने की दिशा में बहुत काम किया है।** उन्होंने यह भी बताया कि हमने पैक के दोनों ओर **85 प्रतिशत चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां दी,** वैश्विक व्यस्क तंबाकू सर्वेक्षण (जीएटीएस) का दूसरा राउंड आयोजित किया, टोल-फ्री नेशनल टोबैको क्विटलाइन और एम-ससेशन सेवाएं शुरू की और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रोग्राम के विस्तार के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आवश्यक निवेश किए हैं, जिनकी डब्ल्यूएचओ ने अपनी वैश्विक तंबाकू नियंत्रण रिपोर्ट, 2015 में चर्चा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि भारत ने धूम्ररहित तंबाकू उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और तंबाकू मुक्त फिल्म और टेलीविजन नीति को सख्ती से लागू किया है।"
2. **27 करोड़ लोगों के साथ भारत तंबाकू का सेवन करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है।** उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्यों को समर्पित तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ बनाने चाहिए। उन्होंने एफएसएसएआई के तहत मंत्रालय द्वारा तंबाकू के इस्तेमाल को नियंत्रण करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला।

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत गौरव अवॉर्ड

अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक जैन **आचार्य डा. लोकेश मुनि एवं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय, न्यूयार्क में भारत गौरव अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।** उन्हें विश्व में अहिंसा, शांति व सद्भावना की स्थापना के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित सम्मान से अलंकृत किया गया। **युनिवर्सल पीस फेडरेशन के अध्यक्ष डा. थॉमस वाल्स तथा वर्ल्ड फेडेरेशन ऑफ यूनाइटेड नातिओंस एसोसिएशंस की चेयरपर्सन आयदूरा किथगवा पुरस्कार प्रदान किया।** समारोह में कई सेनेटर, कोंग्रेस मेन आदि प्रतिष्ठित हस्तियां सम्मलित हुएद्य

क्या है

1. सांस्कृतिक युवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में **श्री श्री रविशंकर** के प्रतिनिधि ने उनका सम्मान स्वीकार किया साथ ही प्रजापति ब्रहमकुमारिज की वरिष्ठ राजयोगिनी **दादी हृदय मोहिनी,** सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पदम विभूषण डा. बिन्देश्वरी पाठक, फिल्म निर्माता पद्मश्री मधुर भंडारकर, टी. वी. एशिया के संस्थापक पदम श्री डा. एचआर शाह, पदम विभूषण डा. कन्तिमल हस्तीमल संचेती, डा. राज भयानि भी सम्मानित हुएद्य
2. इसके अतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा और अफ्रिका की अनेक प्रतिभाएं जिन्होंने विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है सम्मानित किया गयाद्य
3. आचार्य लोकेश मुनि ने सम्मान ग्रहण करते हुए कहा कि भारत विश्व शांति व् मानवता के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा हैद्य विश्व शांति के लिए विकास के लिए शांति आवश्यक हैद्य
4. आज विश्व के कोने-कोने में भारतीय मूल के लोगो ने विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई है।

मालाबार सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं

अमेरिका और जापान के साथ मालाबार सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने के प्रस्ताव को भारत ने फिलहाल नहीं माना है, लेकिन भविष्य में भारत तैयार हो सकता है। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखल के बीच भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले द्विपक्षीय सहयोग चाहता है, फिर बहुपक्षीय सहयोग।

क्या है

1. **मालाबार अभ्यास में भारत के साथ जापान और अमेरिका के नौसैनिक शामिल होते हैं।** साल **2007 तक इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होता था,** लेकिन तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इससे अलग होने का फैसला किया था। अब ऑस्ट्रेलिया इसमें बतौर ऑब्जर्वर शामिल होना चाहता है, लेकिन जुलाई में होने वाले अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को मौका नहीं मिलेगा।
2. राजधानी स्थित अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को मालाबार अभ्यास की आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि इसमें भारत, जापान और अमेरिका हिस्सा लेंगे।
3. माना जाता है कि हिंद महासागर में चीन की दखल रोकने के लिए जापान और अमेरिका अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की भी मौजूदगी चाहते हैं। भारत ने मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
4. कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत नहीं चाहता कि चीन से उसकी तनातनी और गहरा न जाए, लेकिन इस बात को सूत्रों ने खारिज कर दिया। उनका मानना है कि अगले महीने होने वाले मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भले न शामिल हो पाए, लेकिन भविष्य के लिए उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं।

रेमिटेंस प्रवाह में भारत आगे: UN

दुनिया भर में काम करने वाले **भारतीयों ने बीते साल 62.7 अरब डॉलर स्वदेश भेजे** जो इसी अवधि में चीन समेत किसी अन्य देश को मिले **विदेशी मनी-आर्डर में सबसे उपर रहा। संयुक्त राष्ट की इकाई कषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष आईएफएडी** ने अपने एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला है। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के कुल लगभग 20 करोड़ प्रवासियों ने 2016 में अपने अपने घरों को कुल 445 अरब डॉलर धन प्रेषित किया। इससे दुनिया में लाखों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आने में मदद मिली।

क्या है

1. **बीते दशक में रेमिटेंस प्रवाह औसतन 4.2 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढा है** और यह 2007 में 296 अरब डालर से बढ़कर 2016 में 445 अरब डॉलर हो गया।
2. अपनी तरह के इस अध्ययन में 2007 से 2016 के दस साल में विस्थान व रेमिटेंस प्रवाह का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार आलोच्य अवधि में विदेशों से प्रवासियों दवारा भेजे गए कुल मनी आर्डर का 80 प्रतिशत धन 23 देशों को मिला। **इनमें भारत, चीन, फिलिपीन, मेक्सिको व पाकिस्तान प्रमुख हैं।**
3. वहीं जिन देशों से सबसे अधिक मनीआर्डर भेजे गए उनमें **अमेरिका, सउदी अरब व रूस प्रमुख है।** अध्ययन के अनुसार 2016 में भारत विदेश से सबसे अधिक मनीआर्डर पाने वाला देश रहा। उसे 62.7 अरब डॉलर धन मिला। उसके बाद चीन का नंबर रहा जिसे कुल 61 अरब डॉलर की राशि मिली।
4. इसके बाद फिलीपीन को 30 अरब डॉलर व पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर धन मिला। इसके अनुसार 2007-2016 के दशक में भारत ने विदेशी नमी आर्डर पाने के मामले में चीन को पछाड़ दिया।

सुबह छह बजे बदलेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम

एक दिन बाद यानी 16 जून, 2017 से पेट्रोल व डीजल की कीमतों में रोजाना होने वाले बदलाव को लेकर नियमों को थोड़ा बदल दिया गया है। अब **आधी रात के बजाय रोजाना सुबह छह बजे** इसकी कीमतों में बदलाव होगा।

क्या है

1. **डीलरों को रोजाना रात में कीमत बदलने के लिए कर्मचारियों को रखना पड़ता था।** इस वजह से यह फैसला किया गया है कि अब रात्रि के 12 बजे के स्थान पर सुबह छह बजे पेट्रोल व डीजल की कीमतें बदली जाएंगी।
2. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली थोड़ी-बहुत कमी होती है तो उसका फायदा भी ग्राहकों को मिले। इसके साथ ही तेल कंपनियों को कहा गया है कि वे सभी पेट्रोल पंपों को स्वचालित बनाने का काम भी तेजी से शुरू करें। तेल कंपनियों को पेट्रोल व डीजल के उत्पादन से लेकर उसे ग्राहकों को बेचने की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने को कहा गया है।
3. **देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पूरी प्रक्रिया को निर्बाध तरीके से लागू करने के लिए चौबीस घंटे का कंट्रोल रूम बनाने का एलान किया है।** कंपनी पूरे देश में कुल 87 कंट्रोल रूम बनाएगी। कंपनी यह सुनिश्चित कर रही है कि पेट्रोल पंपों को किसी तरह की इंवेंट्री की हानि न हो। इसके लिए 24 घंटे के भीतर डिपो से 25 हजार डीलरों तक पेट्रोल व डीजल पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे पेट्रोल पंपों को नई कीमत के मुताबिक पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति हो सकेगी।

सबसे बड़ी रिफाइनरी

1. तेल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 30 अरब डॉलर (दो लाख करोड़ रुपये) की लागत से देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस रिफाइनरी में आइओसी की हिस्सेदारी 50 फीसद होगी जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम की हिस्सेदारी 25-25 फीसद होगी।
2. आइओसी के चेयरमैन संजीव सिंह, एचपीसीएल के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश कुमार शर्मा और बीपीसीएल के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डी. राजकुमार ने संयुक्त उपक्रम की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये।
3. अधिकारियों के अनुसार देश में ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रत्नागिरी में छह करोड़ टन रिफाइनिंग क्षमता की रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। अभी तक देश में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर में स्थित रिफाइनरी सबसे बड़ी है।

न्यायिक व्यवस्था में PIL को शामिल करने वाले जस्टिस का निधन

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पी.एन.भगवती का 15 जून को निधन हो गया। **वह 95 वर्ष के थे। जस्टिस भगवती देश के 17वें चीफ जस्टिस थे।** उन्होंने12 जुलाई,1985 से 20 दिसंबर, 1986 तक बतौर चीफ जस्टिस सेवा दी थी।

क्या है

1. उन्होंने अपने न्यायिक करियर में **पीआईएल यानी जनहित याचिका को पेश कर काफी चर्चा पाई थी।**
2. 986 में इसे समाज के पिछड़े और सुविधाविहीन लोगों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से पेश किया गया था। इसके बाद से यह न्यायिक व्यवस्था का अहम हिस्सा बन चुका है।
3. **प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान घोषित आपातकाल में वह श्बंदी प्रत्यक्षीकरणश् केस से संबंधित पीठ का हिस्सा थे** और इसको लेकर अपने विवादित फैसले को लेकर भी खासे चर्चा में रहे। हालांकि, 1976 के इस फैसले को 30 साल बाद उन्होंने श्कमजोर कृत्यश् करार दिया था। प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और न्योरोसर्जन एस.एन.भगवती उनके भाई हैं।

22 वां एपीडा वार्षिक पुरस्कार समारोह

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत **कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पादों के निर्यात और विकास के लिए एपीडा सर्वोच्च संस्थान है।** एपीडा के जरिए भारतीय निर्यातकों को न केवल विदेशी वाजार मुहैया होते हैं बल्कि निर्यात के लिए जरूरी तमाम सारी सुविधायें भी उपलब्ध करायी जाती हैं। **एपीडा सहयोगी सेवाओं के अतिरिक्त निर्यातकों के लिए उपयुक्त साझेदार की खोज में भी मदद करती है।** एपीडा के एक्सपोर्ट बास्केट में अचार, चटनी, सॉस, चावल, शहद, ताजी फल और सब्जियां, पेय पदार्थ, खाद्यान, सुंगधित पदार्थ शामिल हैं।

क्या है

1. भारतीय कृषि उत्पादों और प्रसंस्करित खाद्य पदार्थों के निर्यात में बेहतरीन सेवा के लिए **निर्यातकों को 2014-15 और 2015-16 के लिए 82 पुरस्कार अलग अलग श्रेणियों में दिए गए।**
2. **डायमंड श्रेणी में 2, गोल्ड में 33, सिल्वर में 29, ब्रांज में 18 पुरस्कार शामिल थे।** दोनों वित्तीय वर्षों में बेहतरीन निर्यात सेवा के लिए एलन संस लिमिटेड को डायमंड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया ।
3. जिन कंपनियों को दोनों वित्तीय वर्षों के लिए गोल्डन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया, उनमें **रमेश फ्लावर्स प्राइवेट लिमिटेड, नंद्याला सत्यनारायना (ताजी सब्जियों के लिए), नामधारी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड,** अलहम्द एग्रो फुड्स प्राइवेट लिमिटेड (भैसों का मीट), एसकेएम एग प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंडिया लिमिटेड, गुजरात को-ऑप मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, केजरीवाल बी केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, यू.बी. ग्लोबल लिमिटेड, हिन्दुस्तान गम एंड केमिकल्स लिमिटेड और सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे।
4. विजेताओं को वाणिज्य सचिव श्रीमति रीता तेवतिया ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद भी कृषि उत्पादों के निर्यातकों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जिसकी वजह से भारत दुनिया के सातवें बड़े कृषि उत्पाद निर्यातक देशों में शामिल हुआ है।

41 लाख में बिके गांधीजी के चित्र वाले डाक टिकट

दुर्लभ सिक्कों व डाक टिकटों की खरीद फरोख्त करने वाली **ब्रिटिश कंपनी स्टेन्ले गिबन्स ने चार ऐसी डाक टिकटों की बिक्री करके 41 लाख रुपये कमाए हैं, जिन पर महात्मा गांधी का चित्र था।** कंपनी का कहना है कि भारतीय डाक टिकटों की यह अब तक की सबसे ऊंची बोली रही है।

क्या है

1. **इस फर्म की स्थापना 1856 में एडवर्ड स्टेन्ले ने की थी।** डाक टिकटों की नीलामी करने वाली यह विश्व की सबसे पुरानी फर्म है।
2. 1891 में इसने अपना शोरूम लंदन में खोला था। **हांगकांग व सिंगापुर में भी इसकी जड़े फैल चुकी हैं।**
3. कंपनी का कहना है कि गांधी जी के फोटो लगी 1948 में से केवल 13 डाक टिकटें अभी चलन में हैं।
4. दस रुपये की इस स्टांप को आस्ट्रेलिया के एक निजी कलक्टर को बेचा गया। कंपनी का कहना है कि वह अपने विस्तार की योजना पर काम कर रही है, लेकिन अंतिम फैसला संसाधनों की उपलब्धता को देखकर लिया जाएगा।